

साप्ताहिक

शान्ति मिशन

नई दिल्ली

वर्ष-30

अंक- 40

01-07 अक्तूबर 2023

पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

आर्थिक तरक्की में वंचित लाचार

पृष्ठ A 6

साइबर अपराध का बढ़ता ख़तरा

पृष्ठ A 7

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण

नारी शक्तिवंदन बिल सर्वसम्मति से पारित

जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने कुछ आरक्षणों के साथ महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति दिखाई है, वह भारतीय संसदीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसकी सराहना की जानी चाहिए।

अंततः लोगों की समझ में आया और सरकार ने पूर्ण सर्वसम्मति से 'नारी शक्ति वंदन' बिल को मंजूरी दी। राज्यसभा में एक भी आवाज नहीं सुनी गई। अब महिलाओं को भी इंसान माना जाना चाहिए और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें बढ़ा दी जानी चाहिए। आभारी होना निश्चित रूप से एक सुयोग स्वागत है। इस मंजूरी को तारीखी भी कहा जाएगा क्योंकि यह संसद के पहले दिन की कार्यवाही का हिस्सा बन गया है। यह नई संसद हाउस के लिए एक शानदार शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। यह बिल पिछले दशकों से ठड़े बस्ते में जिसे हमारी संसद मंजूरी दे दी। 1966 में लाल बिहार शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी तमाम बाधाओं को पार कर संगठन मंत्रालय पर अपना अधिकार पाने में सफल रहीं और दुनिया भर के पुराने और आधुनिक लोकतंत्रों को बता दिया कि हम संकल्प के दम पर किसी भी बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। खुद को सबसे पुराने लोकतंत्र का प्रणेता कहने वाले अमेरिका में किसी भी महिला को राष्ट्रपति का पद नहीं मिल सकता है। यह भारत का एक रिकॉर्ड और उपलब्धि है जिसने कई विकासशील देशों को रास्ता दिखाया है। आप तो जानते ही होंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं और फिर श्रीतंका और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में महिलाएं प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में सफल होती हैं। जहां तक चुनावी राजनीति का सवाल है मतदाताओं के रूप में महिलाओं ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। 2019 के संसदीय चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों

से अधिक मतदान कर अपनी राजनीतिक जागरूकता साबित की। यह सच है कि महिलाएं अब चुनाव लड़ रही हैं भले ही उनको संसद और विधानसभाओं में अपना पूरा अधिकार न मिल पाया हो, लेकिन उनकी प्रगति जारी है। 2019 के संसदीय चुनाव में जहां वे 15 प्रतिशत तक पहुंचने में कामयाब रहे, वहीं राज्यसभा में उनका प्रतिशत 13 प्रतिशत तक पहुंच गया है। एक अच्छी बात यह है कि हमारे राजनेताओं ने इस स्थिति से निपटने के प्रयास बहुत पहले 1980 में ही शुरू कर दिए थे जब श्री राजीव गांधी ने पंचायत स्तर पर महिलाओं को 23 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था। उद्देश्य यह था कि जब महिलाओं को पंचायतों में ताकत मिलेगी और राजनीतिक चेतना आएगी, तो उनके लिए विधानसभाओं और पार्टियों में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भी इस संबंध में प्रयास किये। देवगढ़ा, गुजरात और मनमोहन आदि सरकारों ने महिला पर्यवेक्षण पर संसद में प्रस्ताव पेश किया लेकिन वे इसे पारित नहीं करा सके। प्रस्तावित सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा में पारित भी कर दिया था, लेकिन लोगों की समझ के कारण कि यह पारित नहीं हो सका, इसे ठड़े बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल, वह गठबंधन सरकारों का युग था। सत्ता बचाने की चिंता बार-बार बेदर्दी से ये बिल पेंडिंग अवस्था में रहा। अब लोकतंत्र की स्थापना के ठीक पचहत्तर साल बाद इस विधेयक को सामने आने का मौका मिला, तो आज जो सरकार सत्ता में है, उसके पास संसद में पूर्ण बहुमत है और भले ही उसने साढ़े नौ

साल अनदेखी में बिताए हों इसकी राजनीतिक समीक्षीयता के बारे में। हमने देर से कहा है कि मोदी सरकार ने देश की पुरुष आबादी को यह अधिकार दिया है और हालांकि महिलाएं अपने अधिकार तक तकाल पहुंच से वंचित हैं, इसलिए उन्हें 2029 से पहले इस कानून से लाभ नहीं होगा। उसे आशा की एक किरण दी है जिससे उसका उत्साह बढ़ा है। महिला आरक्षण बिल की मंजूरी किसी एक पार्टी की नहीं है। यह उन सभी को जाता है जिन्होंने इसके लिए कोई प्रयास किया है। यह भी सच है कि अगले आम चुनाव में जहां बीजेपी अपनी मंजूरी के लिए श्रेय की हकदार नहीं है, वहीं अन्य पार्टियां इसकी खामियों को उजागर करके महिलाओं की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करेंगी, और भले ही इस प्रक्रिया को लगभग सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई हो। लेकिन विपक्ष इसके कार्यान्वयन में कई वर्षों की देरी को जिम्मेदार ठहराया है और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है और कहा जा सकता है कि वह इस बिल को रास्ता देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता

बिल और जेडीयू जैसी प्रांतीय पार्टियां कोने-कोने तक आरक्षण की मांग कर रही हैं। संसद भवन में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से इस बिल का समर्थन किया। यह पिछले तीन दशकों में समाज और राजनीतिक दलों में आए बदलाव का प्रतिबिंब है। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के बाद संसद में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव होंगे :

(1) लोकसभा में महिलाओं की संख्या वर्तमान में 82 से बढ़कर 181 हो जायेगी। (2) इस विधेयक में आरक्षण के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं होगा। (3) लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का 33 प्रतिशत इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। (4) प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि पार्टियों में पूल या शराब पीना, अब आपके पास नौकरी नहीं है, इसलिए यह पार्टियों के लिए उपयोगी है। यह लोकतंत्र के लिए एक प्रयोग होगा।

नारी वंदन शक्ति कानून ने महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और उनके नेतृत्व कौशल विकसित करने के तरीकों को अपनाने का अवसर प्रदान किया है। और पार्टी में, आपके पास मशीन में कम से कम 3 अध्यक्ष हैं, केवल महिलाओं को खाने के लिए आरक्षित होगी। (5) इस विधेयक के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग के कारण यह बिल इतने दिनों से रुका हुआ है। (5) इस विधेयक के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण केवल पंद्रह वर्षों के लिए होगा, जिसके बाद इसे जारी रखने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाएगा।

हमारे विचार में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के लिए केवल आरक्षण ही रामबाण नहीं है। कई देशों में जहां संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, यहां तक यह अधिकार दिया गया है, यहां तक यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन इन देशों में सत्ता में भागीदारी में महिलाओं की क्या स्थिति है? राजीव सरकार देशों में सत्ता में भागीदारी में महिलाओं को क्या स्थिति है? राजीव सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके कुछ प्रांतों में महिलाओं को

इस्लामी दुनिया

। इस्लामी दुनिया । इस्लामी दुनिया

भारत से कुछ तो सीखे पाकिस्तान

मरिआना बावर

वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

हाल ही में भारत ने लगातार तीन बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिन पर पाकिस्तान की पैनी नज़र रही। सबसे पहले भारत का चंद्रयान-3 चांद के अंधेरे हिस्से (दक्षिणी ध्रुव) की तरफ उतरा, जो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना था। उसके बाद जी-20 शिखर सम्मेलन की तस्वीरें सामने आईं, हाजिसके कारण दुनिया भर की नजरें नई दिल्ली पर टिकी थीं। और तीसरी घटना यह है कि कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप क्रिकेट मैच जीत लिया!

नेपाल ही वह देश है, जहां कई सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जीवित देवी हैं। लेकिन मेरे लिए यह भारत की पंद्रहवीं राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मू की तस्वीर थी, जिसमें वह भारतीय देवी की तरह लग रही थीं। यह तस्वीर भारतीय दौरे पर आए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी बैठक के दौरान ली गई थी। तस्वीर में वह अपने सिर पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर शार्ति से बैठी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पाकिस्तानियों का

यान तब आकर्षित किया था, जब उन्हें पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया था। उन्होंने विशेष रूप से समाज के विचित्रों के साथ-साथ हाशिये

पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति के विपरीत,

भारतीय राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मू को संविधान के दायरे में रहकर और किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ाव से दूर रहते हुए देखना अच्छा है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी

ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी से था, संविधान की मांग के अनुसार अराजनीतिक रहने से इन्कार कर दिया है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें इमरान खान के समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ता की तरह काम करते देखा है। हालांकि संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्हें पांच साल के लिए राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो तब तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, जब तक कि नई सरकार नहीं आती है और वह नई सरकार एक नए राष्ट्राध्यक्ष को नामित नहीं करती। राष्ट्रपति के इस्तीफा देने की स्थिति में, संविधान सीनेट के अध्यक्ष को स्वतः राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने की अनुमति देता है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति की गैरमौजूदगी में, सीनेट अध्यक्ष मौजूदा राष्ट्रपति की पूर्ण शक्तियों के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

अतीत में हमने आपातकाल की स्थिति में सीनेट के अध्यक्ष को राष्ट्रपति का बाकी पेज 11 पर

बाकी पेज 11 पर

पाकिस्तान लौट रहे नवाज़ शरीफ फिर करेंगे राजनीति

पाकिस्तान मुसलिम लीग (नवाज़) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की अगले महीने पाकिस्तान वापसी की घोषणा ने राजनीतिक मैदान में एक हलचल पैदा कर दी है। लंदन में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए उनके भाई और निर्वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ का कहना था कि 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान लाहौर में नवाज़ शरीफ का स्वागत करेगा।

ध्यान रहे कि मुसलिम लीग (नवाज़) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ इलाज के लिए सन 2019 में ब्रिटेन चले गए थे और पनामा लीक्स में की ओर से दी गई चार सप्ताह की अवधि में वह वापस नहीं आए जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था, जिसमें उन्हें जमानत भी नहीं मिलनी थी। और अब उन्होंने लगभग चार साल के स्व-निर्वासन

के बाद पाकिस्तान वापस आने की घोषणा की है। नाम आने पर अदालत इसलिए एक ऐसे समय में जब पिछले कई सालों के दौरान उनकी अनुपस्थिति में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा गढ़े गए नकारात्मक प्रचार के कारण उनकी पार्टी की लोकप्रियता और वोट बैंक को धक्का पहुंचा है, उन्हें खुद भी राजनीति से आजीवन अयोग्यता की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इमरान खान कैद में होने के बावजूद जनता में लोकप्रिय हैं। इसीलिये जीव की प्रमुखी के लिए शरीया की वापसी का है जमीन तैयार की जा रही है और जब वह अपने भाई की सरकार के दौर में पाकिस्तान वापस नहीं आए तो अब कहां से क्या भरोसा दिया गया है?

इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक मुजीबुर रहमान

शामी का कहना है कि नवाज़ शरीफ के लिए माहौल काफी साजगार हो चुका है। वर्तमान कार्यवाहक केंद्रीय व राज्य सरकार उनके विरुद्ध कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखती, इसलिए अगर पाकिस्तान वापसी पर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह एक 'साफ्ट' जेल होगी और संभव है उन्हें सशर्त जमानत भी मिल जाए। मुजीबुर रहमान शामी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ के वापस आने से सन 2018 का दृश्य दोबारा दोहराया जा रहा है, बस इस बार पात्रों का अंतर है।

पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक नसीम जोहरा का कहना है कि नवाज़ शरीफ यह समझते हैं कि चूंकि इमरान खान भी जेल में है और नवाज़ को मुकदमों में भी राहत मिल चुकी है या मिल जाएगी तो इसलिए बाकी पेज 11 पर

यह दिल्ली है

। यह दिल्ली है

। यह दिल्ली है

117 करोड़ में एमसीडी की स्वास्थ्य सेवाएं होगी स्वस्थ

दिल्ली सरकार की ओर से अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 117 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से एमसीडी के बड़े अस्पतालों और डिस्पेंसरी में 1720 कार्य किए जाएंगे। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि इस फंड से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार संबंधी कार्य मार्च 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे। एमसीडी के 7 बड़े अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्रसूति केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाओं में सुधार किया जाएगा। मेयर ने सोमवार को निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम में भी स्वास्थ्य मॉडल लागू किया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को भी बेहतर इलाज मिल सके। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को केपिटल और रेवेन्यू हेड के तहत मिला है, जिसे दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार द्वारा केपिटल फंड में 54 करोड़ रुपये और रेवेन्यू हेड में 63 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिन्हें दिल्ली नगर निगम के 7 बड़े अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्रसूति केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर खर्च किया जाएगा। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने बताया कि दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल

हिन्दूराव अस्पताल है, जहां गरीब तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं। केपिटल हेड के तहत मिले फंड से यहां मेजर और माइनर रिपेयर का कार्य करवाया जायेगा। अस्पताल में अलावा एसी प्लांट और लिफ्ट की मरम्मत और रख-रखाव करने का कार्य

किया जायेगा। हिन्दूराव अस्पताल में एनीस्थिसिया वर्क स्टेशन की शुरूआत की जायेगी। कार्डियोलॉजी विभाग के काम पर व्यय किया जायेगा। इसके अलावा एसी प्लांट और लिफ्ट की मरम्मत और रख-रखाव करने का कार्य

प्लास्टिक सर्जरी में उपयोग आने वाले उपकरणों की खरीद की जाएगी। दिल्ली मेडिकल कॉलेज में सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य करवाए जाएंगे। मादीपुर में नये प्रसूति केन्द्र का निर्माण करवाया जा रहा है जोकि नवंबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा।

इन अस्पतालों में ये काम करवाएं जाएंगे

पूर्वी दिल्ली स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल में सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य के अलावा जर्जर पैडे ब्लॉक की मरम्मत करवायी जाएगी।

- सीवर लाइन की मरम्मत का कार्य तथा आईसीयू और आपातकालीन वार्ड के सुधारीकरण और रख-रखाव का कार्य किया जायेगा।

- राजन बाबू टीबी अस्पताल के विभिन्न ब्लॉक और शौचालयों में मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा।

- माता गुजरी अस्पताल में सर्जिकल व आई ओटी के लिए उपकरणों की खरीद की जाएगी।

- कस्तूरबा अस्पताल के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवायी जायेगी।

- पीडीयाट्रिक्स विभाग के लिए ओटोमेटिक और टी टेबल और रिमोट ऑपरेटेड बेड्स की भी व्यवस्था की जाएगी। □□

हाशिये पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का एक अवसर

दिल्ली और देश पर सालों से राज कर रही कांग्रेस दिल्ली में दस साल से हाशिये पर पहुंच गई है। कहा गया कि कांग्रेस ने भाजपा के मध्य वर्ग के मतदाताओं को भाजपा से अलग करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मज़बूत करने में हर तरह से मदद की। यही आरोप भाजपा पर लगा कि वह दिल्ली से कांग्रेस को खत्म करने के लिए आप से केवल दिखावटी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि आप ने इन दस दिल्ली साल में चाहे मुफ्त विजली-पानी के नाम पर या चाहे बढ़िया प्रचार तंत्र का उपयोग करके दिल्ली में अपनी जड़े जमा कर इन अफवाहों को खारिज कर दिया। अब आप दिल्ली की मुख्य राजनीतिक पार्टी हैं। इन दस साल में कांग्रेस को अपने को खड़ा करने के कई अवसर आए लेकिन उसके नेताओं पर सत्ता में रहने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वे उसका लाभ उठा नहीं पाएं और दिल्ली में कांग्रेस अप्रासारिक हो गई। आज भी दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस के 15 साल के शासन को कांग्रेस का स्वर्णिम काल माना जाता है। उनके शासन के दस साल के सहयोगी और किसी गुट विशेष के न माने जाने वाले अरविंद सिंह लवली को दोबारा दिल्ली कांग्रेस की बागडोर सौंप कर कांग्रेस ने अपनी पार्टी को दिल्ली में खड़ा करने का एक अवसर खोजा है। सही मायने में तो हारी-थकी

संपादकीय

शांति मिशन

सत्ताधारी पार्टी के दबाव के बावजूद राहुल गांधी का सफर

जारी है

पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें उनके विरोधियों ने एक तानाशाह और आत्मतुष्ट नेता के रूप में ब्रांड किया था, को 1977 में देश के लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था। यह वह समय था जब मिसेंड्रा गांधी की शास्त्रियत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक मानी जाती थी। श्रीमति इंदिरा गांधी के सत्ता से बेदखल होने से ठीक पांच साल पहले उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश नाम से एक नया देश अस्तित्व में आया। श्री गांधी के मजबूत और प्रभावी नेतृत्व में, भारतीय सेना ने तेरह दिनों के युद्ध के बाद 16 दिसंबर, 1971 को 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और इस निर्णायक जीत के बाद ही भारत एशिया में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। अमीर जिंसी निश्चित रूप से उनके राजनीतिक वर्ग थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के महान राजनीतिक व्यक्तित्व के बावजूद, देश की जनता ने उनके किसी भी तानाशाही प्रयास को स्वीकार नहीं किया और 1977 में आपातकाल के अंत के बाद हुए चुनावों में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। उनको अपदस्थ कर दिया गया, जिसके बाद नई नवेली जनता पार्टी सत्ता में आई और फिर जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आते ही सरकार ने श्रीमति गांधी को प्रताड़ित करना आरंभ किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना और जांच आयोगों का गठन करना आदि शुरू हो गया। जिन लोगों ने जनता पार्टी को सत्ता दी, वे इन सभी स्थितियों और कार्यों को देख रहे थे। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों पर कई मुकदमे लाए गए और आखिरकार अक्टूबर 1977 को शाम 5.20 बजे सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सच तो यह है कि उन्होंने आपातकाल के समय विपक्षी दलों के कई नेताओं को जेल में डाल दिया था, जिनमें चौधरी चरण सिंह और लालचंद आडवाणी भी शामिल थे, इसलिए वे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर उनके और उनके खिलाफ किए गए कथित दुर्व्यवहारों का पर्दाफाश करना चाहते थे। बदला लेने के लिए जेल भेजना, यही कारण था।

समय बदला, श्रीमती गांधी एक बार फिर शानदार तरीके से सत्ता में लौटीं और इससे पहले शायद यही वजह रही होगी कि इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए की गई। इस की गिरफ्तारी को ऑपरेशन ब्लंडर कहा गया। सरकार के आदेश पर, सीबीआई अधिकारियों ने अदालत से तत्काल जमानत का मौका बदलने के लिए इंदिरा गांधी को शाम 5:00 बजे गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कम से कम एक रात जेल में बितानी पड़ी, हालांकि बिना किसी सबूत के, केवल बदला लेने के लिए। श्री गांधी की आग बुझाने के लिए की गई इस गिरफ्तारी पर कार्यवाही शुरू हुई और अदालत ने श्री गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत मांगे, अभियोजक ने हालांकि साहसपूर्वक इंदिरा गांधी को दोषी घोषित कर दिया, लेकिन इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। नतीजा यह हुआ कि अदालत ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बरी कर दिया और केवल ढाई साल बाद जब जनता पार्टी में झगड़ा शुरू हुआ, तो श्रीमती गांधी की राजनीतिक इच्छाशक्ति ने काफी हद तक असंभव को भी संभव बना दिया। श्री मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन वह एक कमजोर राजनेता थे, उन्होंने संसद का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1979 में देश में लोकसभा की स्थापना हुई। उपचुनाव हुए और जनता ने एक बार फिर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता सौंपी और इस तरह महज़ ढाई साल पहले तानाशाही के आरोप में सत्ता से बेदखल हुई इंदिरा गांधी की वापसी हुई सत्ता में। शानदार अंदाज में सत्ता में वापसी की और शायद यही कारण रहा कि इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए उनकी गिरफ्तारी को ऑपरेशन ब्लंडर कहा गया। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश एक बार फिर कुछ वैसा ही या उससे भी बुरा कुछ देख रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके विचारक जो कर रहे हैं वह वर्तमान शासक नहीं कर रहे हैं और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उनके चरित्र और राजनीतिक निर्णयों की आलोचना की जा रही है। इसने संवेदनशील वर्ग और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या जिस दिशा में हमारे वर्तमान शासक जा रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा नेताओं खासकर श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी, जो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, को कई मामलों में फँसाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में पचहत्तर वर्षीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच कार्यालय लाया गया और कई घटों तक पूछताछ की गई। श्री राहुल गांधी से तीन चरणों में 50 घटों तक पूछताछ की गई है, जो शुद्ध राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। वास्तव में, सांप्रदायिक तत्व और दक्षिणपंथी, विशेषकर आरएसएस से जुड़े लोग, न केवल नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी से नफरत करते हैं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी से भी नफरत करते हैं, क्योंकि यह यह भी स्पष्ट है, क्योंकि यह परिवार और अंततः पार्टी भारत की आत्मा में समाहित धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। जबकि हमारे वर्तमान शासक और उनकी केंद्रीय सत्ता घोर सांप्रदायिक सोच रखती है, समय-समय पर सत्ता के गलियारे भारत के प्रति कांग्रेस की आवाज बुलंद करते रहते हैं। गांधी नेहरू परिवार की तरफ के लिए ये सिलसिला लगातार सामने भी आ रहा है। इसका एक कारण यह है कि कोई भी विपक्षी नेता अभी तक वह साहस नहीं दिखा पाया है जिस साहस के बल पर श्री राहुल गांधी सत्ता की दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। राहुल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है। इन्हें डराना कोई आसान काम नहीं है। राहुल गांधी, जो अपने पिता राजीव गांधी और वादी इंदिरा गांधी जैसे शहीदों की गोद में पले-बढ़े हैं, कम से कम वे लोग जिनकी अपनी कोई पृष्ठभूमि, मूल्य और संस्कृति नहीं हैं और जो अंग्रेजों को खुश करने के लिए नफरत से पले-बढ़े हैं। वे राहुल को धमकी देने में सफल हो गए? इसी प्रयास के तहत भाजपा शासित विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ

तारीखे इरान

सिरतुनबी स.अ.स. पर लिखी गई सबसे तप्सीली किताब

अर-रहीकूल मरातूम

लेखक: मौलाना सफीउरहमान मुबारकपुरी किस्त 22

धार्मिक स्थिति

जिस समय इस्लाम सूर्य उदित हुआ है, यही दीन-धर्म थे जो अरब में पाए जाते थे, लेकिन ये सारे धर्म टूट-फूट के शिकार थे। मुश्किल जिनका दावा था कि हम दीने इब्राहीमी पर हैं, इब्राहीमी शरीअत के करने, न करने के आदेश से कोसों दूर थे। इस शरीअत ने जिस नैतिकता की शिक्षा दी थी, उनसे इन मुश्किलों का कोई ताल्लुक न था। उनमें गुनाहों की भरमार थी और लम्बा समय बीतने के कारण इनमें भी बुत परस्तों की वही आदतें और रस्में पैदा हो चली थीं, जिन्हें धार्मिक अंधविश्वास का पद प्राप्त है। इन आदतों और रस्मों ने उनके सामूहिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर बड़े गहरे प्रभाव डाले थे।

यहूदी धर्म का हाल यह था कि वह मात्र दिखावा और दुनियादारी का नाम था। यहूदी रहनुमा अल्लाह के बजाए स्वयं रब बन बैठे थे, लोगों पर अपनी मर्जी चलाते थे और उनके दिलों में आने वाले विचार और होंठों की हरकत तक का हिसाब करते थे। उनका सारा ध्यान इस बात पर टिका हुआ था कि किसी तरह माल और सत्ता प्राप्त हो, भले ही दीन बर्बाद हो जाए और नास्तिकता और अनीश्वरवाद को बढ़ावा मिलने लगे और उन शिक्षाओं के प्रति अनादर-भाव ही क्यों न जन्म ले ले, जिनकी पावनता बनाए रखने का अल्लाह ने हर व्यक्ति को आदेश दिया है और जिन पर अमल करने पर उभारा है। इसाई धर्म एक न समझ में आने योग्य बुत परस्ती का धर्म बन गया था। उसने अल्लाह और इंसान को अनोखे ढंग से मिला-जुला दिया था, फिर जिन अरबों ने इस धर्म को अपनाया था, उन पर इस दीन का कोई वास्तविक प्रभाव न था, क्योंकि उसकी शिक्षाएं उनके जीवन के असल तौर-तरीकों से मेल नहीं खाती थीं और वे अपने तरीके छोड़ नहीं सकते थे अरब के बाकी दीनों के मानने वालों का हाल मुश्किलों ही जैसा था, क्योंकि उनके मन एक थे, मान्यताएं एक थीं और रस्म व रिवाज मिलते-जुलते थे।

अज्ञानी समाज की कुछ झलकियां

अरब प्रायद्वीप की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के जान लेने के बाद अब यहां की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्थिति की संक्षिप्त रूप-रेखा पेश की जा रही है। (जारी)

कई मामले दर्ज कराए गए हैं। अभी कुछ महीने पहले ही गुजरात के सूरत की एक निचली अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता के तहत सज़ा मिली। उनको आपत्ति करने पर अदि कात्मदार दो वर्ष की कैद का प्रावधान है और जब राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हैरानी की बात है कि वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद लोकसभा सदस्यता ने तुरंत राहुल की लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी और कुछ ही दिनों में सरकार ने उनका आधिकारिक बंगला खाली कर दिया, जिसके बाद आखिरकार उन्हें अपनी सज़ा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में यहां तक कहना पड़ा कि द्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारण और आधार के अधिकतम दो साल की सज़ा दी है। अगर सज़ा दो साल एक दिन से कम होती तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म नहीं होती। इससे देश की जनता को स्पष्ट संदेश दिया गया कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने और गंभीर सवालों से बचने के लिए किया गया था। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासकों के साथ किया था। और वे उनकी धमकी से नहीं डरते और आपको परेशान कर रहे हैं। उसी तरह, राहुल सरकार के दबाव और साजिश की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गांधीजी के रास्ते पर आगे बढ़ती नज़र आ रहे हैं।

एक साल के भीतर फिर से पटरी पर लौट आएगा हिमाचल मुख्यमंत्री

बरसात का मौसम हिमाचल में सबसे रुमानी मौसम रहता है। दूर पहाड़ पर जब बादल घुमड़ना शुरू करते हैं तो वादियां मध्यूर धुन पर नाचने लगती हैं। लेकिन इस बार ऐसी बरसात हुई कि उसने सारी तस्वीर ही बदल डाली। प्रकृति ने ऐसा प्रलय किया कि जहां देखो लोगों की। चीख पुकार, बाढ़ ने ऐसे जख्म दिए कि लोगों को उससे उबरने में उम्र लग जाएगी। करीब 3 हजार घर पूर्णतया ध्वस्त हो गए तो 10 हजार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। चार सौ से अधिक लोगों की जान चली गयी। सड़कों, भूमि के बहने का तो पूरा हिसाब लगाना ही मुश्किल है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बरसात ने तबाही न मचाई हो। ऐसे में सरकार के सामने अब हिमाचल के पुनर्निर्माण की चुनौती है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे इसे लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से विशेष बातचीत की। पेश हैं उसके प्रमुख अंश...

सवालः- नुक्सान बहुत ज्यादा हुआ है। कितना बक्त लग जाएगा इस त्रासदी से उबरने में...?

जवाबः- यह हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। मैंने अपने जीवनकाल में इतनी तबाही नहीं देखी न ही बुजुर्गों से ऐसा सुना। करीब 400 लोग हमें छोड़ कर चले गए। पानी, सिंचाई की हजारों योजनाएं बह गई। घर, सड़क सब बह गया। मैं इन्यावादी हूँ प्रदेश के कर्मचारियों का अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, विद्यायकों का जिन्होंने 48 घंटों के भीतर-भीतर बिजली पानी बहाल किया। अब लोगों के घरों, सड़कों आदि के पुनर्निर्माण का काम है। एक एक प्रभावित का पुनर्वास करेंगे। उसके। लिए धन लगेगा, लेकिन हम कृतसंकल्प हैं कि सबकी पूरी सहायता हो।

सवालः- लेकिन यह धन आएगा कहाँ से सरकार के पास तो इतना पैसा है। नहीं। केंद्र की मदद के बिना यह संभव नहीं है। क्या वो मदद आ रही है जो चाहिए।

जवाबः- बिलकुल यह सब केंद्रीय मदद के बिना संभव नहीं है। हम हर केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं। सबसे मदद मांग रहे हैं। हम संघीय दौँचे में रहते हैं। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य का तो केंद्र की मदद के बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है। हमारा नुक्सान करीब 12 हजार करोड़ का है। इसकी भरपाई करने में समय लगेगा लेकिन हम विश्वस्त हैं कि एक साल के भीतर फिर से वही हिमाचल बना डालेंगे जो बाढ़ से पहले था और उजड़ गया है। इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे।

सवालः- आप लगातार इसे राष्ट्रीय

आपदा घोषित करने की मांग का रहे हैं। लेकिन प्रदेश बीजेपी इस पर कोई रिस्पांस नहीं दे रही।

जवाबः- ये तो बीजेपी जाने कि वो ऐसा क्यों कर रही है लेकिन इतना जरूर है कि ये मांग कांग्रेस सरकार की नहीं है।।। ये हिमाचल की मांग है। और वे भी हिमाचल का हिस्सा हैं। जनता देख रही है। जहां तक हमारी सरकार की बात है हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिसका भी नुक्सान हुआ है उसकी हर संभव मदद होगी।

हमारे जितने भी संसाधन हैं उन सबको लगाकर हम सबकी पूरी मदद करेंगे। जहाँ नियम-कानून बदलने होंगे वहाँ वो काम भी किया जाएगा। कोई बिना मदद के नहीं रहेगा। जो मुआवजा राशि थी वो अब तक सिर्फ 5 हजार थी हमने उसे बढ़ाकर ज्यादा किया

है। पशुओं तक का मुआवजा बाध्य है। कुछ चीजें रही हैं जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में पूरा किया जाएगा। जमीन देनी पड़ेगी जमीन देंगे, पैसा देना पड़ेगा पैसा देंगे। सबको दोबारा बसाएंगे।

सवालः- केंद्रीय मदद को लेकर बड़ा कन्प्यूजन है, वास्तव में अब तक कितनी मदद मिली है।

जवाबः- अब तक जो भी पैसा आया है वह आपदा प्रबंधन का वो पैसा है जो हमें हर साल मिलना तय ही था। उसकी दो किस्तें आती हैं। पहली जुलाई तो है दूसरी दिसंबर में आती है। आपदा आए या न आए वो मिलनी ही होती है। उन्होंने जुलाई वाली किस्त जुलाई में दी और दिसंबर की एडवांस में दे दी। सच्चाई यह है। इसके अतिरिक्त जयराम सरकार के

समय की 315 करोड़ की जो मदद एजी के ऑफिशियल के कारण पैटिंग थी उसमें से 189 करोड़ आया है। और इसके अतिरिक्त दक्षता को 200 करोड़ आया है और कोई पैसा ऐसा नहीं आया है जो सिर्फ इस नुक्सान की मदद हो। जो भी आया रुटीन का पैसा आया है। बी.जे.पी। गुमराह करना छोड़। हाँ..। हिमाचल के लिए मदद दिलाने के लिए आगे आए।

सवालः- मंदिरों के पैसे से भी मदद लेने को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है। वहाँ भी खूब फंड है।

जवाबः- देखें सच तो यह है कि वो पैसा भी लोगों का है, लोगों को ही देना है, मदद करनी है। आस्था का विषय है इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि लोग आहत हों, मंदिर कमेटियां खुद। आगे आकर

ऐसा करें तो ज्यादा बेहतर। मंदिर द्रस्ट मदद कर भी रहे हैं। तो अभी और देखते हैं कि क्या करना है।

सवालः- टूरिज्म प्रदेश मुख्य उद्योग है। उसे पटरी पर लाने के लिए कोई विशेष योजना?

जवाबः- टूरिज्म का पिछले दो महीनों में ही बड़ा नुक्सान हुआ है। जी.एस.टी। के लिहाज से हम माइनस 8 पर चले गए हैं। इसके अतिरिक्त आबकारी कर, का नुक्सान हुआ है।

इन्हीं दो सैक्टरों में 2 हजार करोड़ का नुक्सान हुआ है जो बरसात से हटकर है। लेकिन सब जब जल्द ठीक होगा। हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।

सवालः- कर्मचारी चयन आयोग भ्राताचार का अड्डा बन गया था..?

जवाबः- कर्मचारी चयन आयोग भ्राताचार का अड्डा बन चुका था। इसलिए उसे बंद करना जरूरी था।

दीपक सानन कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है, दूसरी अक्टूबर में आ जाएगी। हम जल्दी ही नया चयन आयोग स्थापित करेंगे और भर्ती परीक्षाएं शुरू होंगी। और रही आयु सीमा की बात हम आयुसीमा में छूट देंगे ताकि किसी का नुक्सान ना हो।

हम बी.जे.पी। सरकार नहीं हैं, के पेपर बिक रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भर्तियां हो रही वो कोर्ट में फंस रही और किसी को कोई फर्क नहीं ये सारा स्थापा बी.जे.पी। का डाला हुआ है। हम तो सिर्फ उसे भुगत रहे हैं। लेकिन सब ठीक करेंगे और सबको बराबर मौका मिलेगा नौकरी के लिए योग्यता ही एकमात्र पैमाना होगा।

सवालः- जिस तरह विश्व को समाधान खोजने का मंच देने की कोशिश की है, उसे देखते हुए क्या जी-20 संयुक्त राष्ट्र का काम नहीं करने लगा है? **जवाबः-** इसमें कोई दो राय नहीं कि नई दिल्ली घोषणा पत्रा जैसा प्रपत्रा पहले कभी जी-20

या किसी दूसरी बहुदेशीय संस्था से नहीं निकला। प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी-20 में शामिल सभी देशों ने जिस तरह वर्तमान की बड़ी-बड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर आम सहमति बनाई, उससे यह साफ हो गया कि इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कई गुना ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ बातें होती हैं। सुरक्षा परिषद में तो कोई काम नहीं कर रहा। जी-20 बड़े मुद्दों पर विमर्श करता है और अगर भारत जैसा नेतृत्व हो तो सभी को मिलाकर फैसले भी हों, सकते हैं। नई दिल्ली में जो फैसले हुए हैं, हम उनके क्रियान्वयन में भी सहयोग करेंगे।

सवालः- मोदी सरकार में कई योग्य ब्यूरोक्रेट हैं। क्या आपकी भी राजनीति में रुचि है? **जवाबः-** नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि सिर्फ इसमें है कि मुझे जो काम दिया गया है उसे जी-जान से करूँ। □□

सवालः- आप लगातार सक्षम लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं अब तक लोगों ने कितनी मदद की।

जवाबः- पूरी हिमाचल मदद को उमड़ पड़ा है। हर संस्था, हर व्यक्ति

बाकी पेज 11 पर

15 बार लगा की नहीं बन सकेगी साझा घोषणा पत्र पर सहमति : अमिताभ कात

सवालः- जी-20 को बहुत सफल बताया जा रहा है। यूक्रेन को लेकर जारी तनाव के बावजूद साझा घोषणा पत्र जारी करने पर बनी सहमति को ऐतिहासिक माना जा रहा है? ऐसा क्यों माना जाना चाहिए?

जवाबः- जी-20 एक ऐसी बहुदेशीय संस्था है जिसमें आम सहमति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ हर सदस्य को वीटो का अधिकार है। इस समूह में विकासशील देश भी हैं, विकसित देश भी हैं। एक दूसरे के धूर-विरोधी देश भी हैं और ऐसे भी हैं जिनमें हाल में तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में जिस घोषणा पत्र पर सहमति बनी, उसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं और 25 प्रपत्रा संलग्न हैं। जितने भी मुद्दे शामिल हैं, उन सभी पर सभी देशों की सहमति है। यूक्रेन-रूस से जुड़े आठ पैरा पर भी सभी देशों की सहमति थी। यह बताता है कि भारत के पास दुनिया के ऐसे संगठन का नेतृत्व करने की क्षमता है जिसमें रुस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ कई विकासशील देश हों। इन सभी देशों के बावजूद यह सहमति बनी रही है।

सवालः- सहमति में शामिल होने वाला आखिरी देश कौन था।

जवाबः- मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आखिरकार सब राजी हुए यह बड़ी बात थी।

सवालः- कहा जा रहा है कि भारत ने इस बैठक को कुछ ज्यादा ही तवज्ज्ञ दी। बहुत ज्यादा खर्च की भी बात हो रही है? आपकी प्रतिक्रिया?

जवाबः- जो बजट था, हमने उससे कम ही खर्च किया। दूसरी बात जी-20 बैठकें दूसरे देशों में एक या दो शहरों में होती हैं, जबकि भारत सरकार ने इसे आम जनता तक ले जाने का फैसला किया था। इस कारण हमने 60 शहरों में इसका आयोजन किया। 200 से ज्यादा बैठकों में एक लाख से ज्यादा विदेशी मेहमान आए। इससे इन शहरों में सुधार का मौका मिला। हमने इस

बात पर जोर दिया कि इन सभी शहरों की कला एवं संस्कृति को विश्व पटल पर प्रसिद्धि मिले। हर बैठक में एक जिला एक उपाद योजना को प्रोत्साहित किया गया। होटलों एवं कारोबारियों को काफी फायदा हुआ। हर राज्य को अपनी ब्रांडिंग

अब अदालतें भी चिंतित हैं माता-पिता की उपेक्षा औं पर

नये बन रहे समाज एवं पारिवारिक संरचना में माता-पिता का जीवन एक त्रासदी एवं समस्याओं का पहाड़ बनता जा रहा है, समाज में बच्चों के द्वारा बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षाओं एवं उनके प्रति बरती जा रही उदासीनता इतनी अधिक बढ़ गई है कि अदालतों को दखल देना पड़ रहा है। माता-पिता भोजन-पानी, दवाई, जरूरत की चीज़ों से महसूल ही नहीं हो रहे हैं बल्कि उनके सम्मान की स्थितियां भी नगण्य होती जा रही हैं। बृद्ध माता-पिता की यह दुर्दशा एक विकाराल समस्या के रूप में उभर रही है। सुविधावाद, भौतिकता एवं धन के बढ़ते वर्चस्व के बीच माता-पिता अपने ही बच्चों की प्रताड़ना के शिकार है। ऐसी बढ़ती समस्याओं पर नियंत्रण के लिये अदालतों को न सिर्फ दखल देना पड़ रहा है बल्कि बच्चों को पाबंद करना पड़ रहा है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करें और उनको सम्मान दें। मद्रास उच्च न्यायालय का ऐसा ही एक फैसला आज के समाज में खून के रिश्तों पर सवाल खड़ा करने वाला है।

न्यायालय ने अपने फैसले में साफ किया है कि बुजुर्ग अभिभावकों की इच्छा पूरी करना बच्चों का दायित्व है। न्यायालय का यह फैसला सिर्फ किसी बच्चे और अभिभावकों के बीच संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं है। इसे व्यापक अर्थों में देखने और समझने की जरूरत है। संवेदनशील मानसिकता के निर्माण से समाज का माहौल बदल सकता है। अदालत चाहती है। कि बृद्ध माता-पिता को उदासीनता एवं उपेक्षा से मुक्ति देकर उन्हें सुरक्षा कवच मानने की सोच को विकसित किया जाये। ताकि एक आदर्श परिवार की संरचना को जीवंत किया जा सके एवं बृद्ध स्वास्थ्य, निष्कंटक एवं कुंठारहित जीवन को प्रबंधित किया जा सकता है। बृद्धों को बंधन नहीं, आत्म गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा को अदालत ने उजागर कर समाज को जागृत करने का सराहनीय काम किया है। ऐसा युग जहां रिश्तों की जगह धन हावी होता जा रहा है। इसी कारण बृद्धों को लेकर गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, ये समस्याएं अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते समाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण खड़ी हुई हैं। चिन्तन

का महत्वपूर्ण पक्ष है कि बृद्धों की उपेक्षा के इस गलत प्रवाह को रोके, इसी बात पर अदालत ने अपने फैसले में बल दिया है।

क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने न केवल बृद्ध माता-पिता के जीवन को दुश्वार कर दिया है बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि जो माता-पिता कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की भरपूर कोशिश करते हैं, उन्हीं मां-बाप के बुजुर्ग होते पर बच्चे उनकी देखभाल से जी क्यों चुराने लगते हैं? बच्चों की नजर मां-बाप की संपत्ति तक ही सीमित होकर क्यों रह जाती है?..। ऐसी बात नहीं है कि सभी बच्चे अपने मां-बाप की उपेक्षा कर

रहे हैं, लेकिन आसपास नजरें घुमाने पर ऐसे मामले हर कहीं नजर आ जाते हैं। जाहिर है ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि बृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा सहमा खड़ा है, बृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सुसंकृत परिवार परम्परा पर काला दाग बनता जा रहा है। अदालत की यह संवेदनशील सोच, है जिससे बच्चों एवं माता-पिता के बीच बढ़ते फासलों को दूर किया जा सकता है,, अदालत चाहती है कि ऐसा परिवार निर्मित हो जिसमें परिवार के बृद्ध हमें कभी बोझ के रूप में दिखाई न दें, हमें यह कभी नहीं सोचना पड़े, कि इनकी उपस्थिति हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है। उन्हें परिवारिक धारा में बांधकर

रखा जाये। लेकिन हम सुविधावादी एकांगी एवं संकीर्ण सोच की तंग गलियों में भटक रहे हैं तभी बृद्ध माता-पिता की आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से बृद्ध माता-पिता को मुक्ति दिलानी होगी। सुधार की संभावना हर समय है। हम परिवारिक जीवन में बृद्ध माता-पिता को सम्मान दें, इसके लिये सही दिशा में चले, सही सोचें, सही करें। बृद्ध माता-पिता से जुड़े मामलों का बोझ अदालतों में बढ़ना एक गंभीर समस्या है, इसके लिये आज विचारकांति है ही नहीं, बल्कि व्यक्तिक्रांति एवं परिवार- क्रांति की जरूरत है। हमारा भारत तो बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि माता-पिता की आज्ञा से श्रीराम जैसे पुरुषों ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया, मातृ-पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अन्धे माता पिता को कावड़ में बैठाकर चारांग की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में बृद्ध माता-पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं।

इस समस्या की शुरूआत तब होती है, जब युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को उपेक्षा की निगाह से देखने लगती है और उन्हें बुढ़ापे और अकेलेपन से लड़ने के लिए असहाय छोड़ देती है। आज बृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, कटुकितांयां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर- उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता। इन्हें स्थितियों से जुड़े मामले न्याय पाने के लिये अदालत की शरण लेते हैं। माता-पिता की उपेक्षा करने वाले बच्चे यह क्यों नहीं समझते कि उम्र के जिस दौर से उनके माता-पिता गुजर रहे हैं, कल उसका सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। विचारणीय सवाल, यह है कि क्या न्यायालय का काम बच्चों को मा-बाप की सेवा करने की नसीहत देने का होना चाहिए? जापानी सिर से ऊपर गुज़रने लगता है, तब न्यायालयों को ऐसे, मामलों में कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और तीखी टिप्पणी करनी पड़ती है। भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की सोच रखने वाला श्वेश है। ऐसी सोच, जिसमें पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसे विलक्षण विचार को जन्म देने वाले देश में यदि बच्चे अपने मां-बाप की देखभाल से बचने लगें और उनका अपमान तक करने लगें, तो चिंता होना शू स्वाभाविक है। एकल परिवारों की वजह से भी यह समस्या बढ़ी है।

दुनिया में तकनीक का दौर बढ़ रहा है। ऐसे में हर शख्स को समय के साथ खुद को ढाल लेना चाहिए नहीं तो वह पिछड़ जाएगा। खासकर ए.आई। तकनीक ने लोगों को काफी डरा दिया है। हाल ही में एडटेक कम्पनी एमेरिटस की 'एमेरिटस ग्लोबल वर्कप्लेस, स्किल्स स्टडी' से यह बात सामने आई है कि टैक्नोलॉजी में आए बदलावों के कारण भारतीयों में कौशल बढ़ाने की इच्छा बढ़ी है। चार में से तीन कामकाजी पेशेवरों का मानना है कि अगर उन्होंने अपना कौशल विकसित नहीं किया तो टैक्नोलॉजी उनकी नौकरियों की जगह ले लेगी। कम्पनी की रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत भारतीयों को डर है कि जब तक वे कौशल नहीं बढ़ाएंगे तो टैक्नोलॉजी उनकी नौकरियों की जगह ले लेगी। इसमें कई उद्योग शामिल हैं।

विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों में बदलती टैक्नोलॉजी के कारण नौकरी जाने का डर है। 83 प्रतिशत लोग एक प्रतिष्ठित माध्यम से कौशल बढ़ाने के इच्छुक हैं। इस सर्वे में 21 से 65 वर्ष की आयु के 6,600 पेशेवरों से बातचीत की गई, ताकि यह समझा जा सके कि वैश्विक कार्यक्रम इससे निपटने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का लाभ वैसे उठा रहा है। □□

रोज़गार

बोलने में माहिर है तो बन सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर

कई बार किसी की बोली बात जिंदगी में लंबे असे तक हमें प्रेरित करती रहती है, जिससे प्रेरित होकर हम अपने मुश्किल समय का सामना आसानी से कर लेते हैं। अगर आप में यह हुनर है तो मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हैं।

इस पेशे की अनेक खूबियों में एक यह है कि इसमें एक जगह बैठ कर काम करने की बंदिश नहीं है, वहीं दूसरी ओर की गई मेहनत का रिटर्न भी आकर्षक होता है जीवन में मोटिवेशन के होने से जिंदगी जीने का मकसद पता चलता है। तमाम परेशानियों के बावजूद आप हसल (मेहनत करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो कहीं-कहीं कोई न कोई मोटिवेशन जरूर होती है। वहीं अगर आप कभी किसी परेशानी को लेकर संदेह में होते हैं तो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो या उद्धरण पढ़ कर आप मोटिवेशन से भर जाते हैं।

मोटिवेशनल स्पीकर कौन होते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर वे हैं जो लोगों को खुद को अगे बढ़ने के लिए मोटिवेट यानी प्रेरित करके उनकी सहायता करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अपने क्षेत्रध्विषय में एक्सपर्ट और प्रोफेशनल होते हैं जो कुछ सलाह और गाइडलाइंस भी प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं।

वे लोगों की स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं और उन्हें अपने टैलेंट, क्षमताओं और जुनून की याद दिलाते हैं। कैसे करते हैं काम

मोटिवेशनल स्पीकर
कुछ भी शुरू करने से पहले लोगों

चाहिए।

मोटिवेशनल स्पीकर बनने के यह भी जरूरी है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हों।

नहीं सीखा कौशल तो चली जाएगी नौकरी

दुनिया में तकनीक का दौर बढ़ रहा है। ऐसे में हर शख्स को समय के साथ खुद को ढाल लेना चाहिए नहीं तो वह पिछड़ जाएगा। खासकर ए.आई। तकनीक ने लोगों को काफी देखभाल से बचने लगें और उनका अपमान तक करने लगें, तो चिंता होना शू स्वाभाविक है। एकल परिवारों की वजह से भी यह समस्या बढ़ी है।

स्वच्छ जीवन एवं सुविधावाद ने भी इस समस्या को गहराया है, तभी बृद्ध माता-पिता इतने कुंठित एवं उपेक्षित होते जा रहे हैं। सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उन्हें बृद्धों को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू करना चाहिए, ताकि बृद्धों की प्रतिभा, कौशल एवं अनुभवों का नये भारत सशक्त भारत के निर्माण में समुचित उपयोग हो सके एवं आजादी के अमृतकाल को वास्तविक रूप में अमृतमय बना सके। अपने को समाज एवं परिवार में एक तरह से निष्प्रयोज्य समझे जाने के कारण बृद्ध माता-पिता सर्वाधिक दुःखी रहता है। □□

इस्लामी दुनिया

पाक में रॉकेट लान्चर शेल में विस्फोट से नौ लोगों की मौत

कराची, : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बुधवार को एक मकान में रॉकेट लॉन्चर पोल में विस्फोट होने से पांच एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कशमोर-कंधकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहिल खोसा ने बताया कि मैदान में खेलते समय बच्चों को एक राकेट लान्चर शेल मिल गया और वे उसे अपने घर ले आए। उन्होंने बताया कि घर में उसमें विस्फोट हो गया और पांच बच्चों और दो महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में पांच अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

संघर्ष में हमारे 192 सैनिक मारे गए : अजरबैजान

बाकू, : अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नागोर्नो-काराबाख में पिछले सप्ताह संघर्ष में अजरबैजान के 192 सैनिक मारे गए और 511 सैनिक घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष के दौरान अजरबैजान के एक आम नागरिक की भी जान चली गई। इससे पहले, नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने कहा था कि संघर्ष में 10 नागरिकों सहित उनके पक्ष के कम से कम 200 लोग मारे गए और 400 से अधिक घायल हुए हैं।

ईरान ने इमेजिंग सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का किया दावा

तेहरान : ईरान ने दावा किया कि उसने एक इमेजिंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस कदम से पश्चिम देशों के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका है। जिन्हें आशंका है कि ईरान इन उपग्रहों का इस्तेमाल परमाणु हथियार विकसित करने में कर सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी 'ईरान' की खबर के अनुसार, ईरान के संचार मंत्री इसा जारेपुर ने कहा कि 'नूर-3' उपग्रह को पृथ्वी की सतह के ऊपर 450 किलोमीटर पर कक्षा में स्थापित किया गया है।

सिंगापुर में यात्री पर नस्लवादी टिप्पणी को लेकर चीनी कैब चालक निलंबित

सिंगापुर : सिंगापुर में चीन के एक कैब ड्राइवर द्वारा एक महिला और उसकी बेटी को भारतीय मूल का नागरिक समझकर उन पर कथित रूप से नस्लभेदी टिप्पणी करने के बाद निजी कार संचालन कंपनी 'टाडा' ने उसे निलंबित कर दिया है। कंपनी ने यह जानकारी दी।

आर्थिक तरक्की में विविध लायर

देश की आर्थिक प्रगति का प्रश्नसितायान केवल स्वेशी मंचों से नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंचों से भी हो रहा है। जो देश विश्व में आर्थिक तरक्की के दसवें पायदान पर था, वह देखते ही देखते पांचवें पायदान पर आ गया और अब घोषणा से दो वर्ष पहले तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की संभावना को पोषित कर रहा है, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में जब दुनिया के बाहुबली देश आर्थिक तरक्की की विस्तृती हुई दर का सामना कर रहे हैं, हमारे देश ने आसानी से आर्थिक मंदी के संकट से बच कर सबसे ऊंची आर्थिक दर का प्रदर्शन कर दिया। विदेशी निवेश भगोड़ा हुआ तो हमारे घरेलू निवेश में उसकी कमी को पूरा करके शेयर बाजारों की चमक-दमक को कम नहीं होने दिया। अब तो 'चीन प्लस' निवेश के घातावरण का जमाना है, जिसमें दुनिया के निवेशकों के लिए एकपात्रा निवेश स्थल चीन नहीं रह गया, बल्कि भारत भी अपने स्थायी नेतृत्व, अपनी सशक्त श्रमशीलता और विस्तृत मांग के साथ उसका स्थान लेने के लिए अग्रसर हो रहा है। मगर ऐसे घातावरण में हम जब देश की पहली पहचान कृषि क्षेत्रा या देश के श्रमिक की ओर देखते हैं, जो कि हमारे देश की आवादी का आधा भाग है, तो लगता है कि उनके कल्याण और उनके बेहतर जीवनस्तर की घोषणाएं पूरी क्यों नहीं हो रही? क्यों किसान आज अपनी आय को दोगुना होता हुआ पाने के स्थान पर एक ऐसी मजबूरी से ग्रस्त हैं कि उनकी आप खेतीबाड़ी की लागत से कम होकर खेती को पाटे का सौदा बना रही है। इसीलिए आज देश में खेतीबाड़ी जीने का ढंग नहीं, बल्कि एक घाटा उठाता हुआ धंधा बन रहा है। इस देश में जहाँ महामारी का विकट संकट गुजर जाने के बाद दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अरबपतियों ने खरबपतियों का और करोड़पतियों ने अरबपतियों के रूप में अवतरण किया है, वहाँ देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद का सपना क्यों व्यर्थ होता जा रहा है, जबकि गरीब, निम्न मध्यवर्ग और मध्य नजर आता है और देश में अमीर-गरीब का भेद असमानता की सब रेखाएं पार कर रहा है। राष्ट्रीय ख्यकी कार्यालय यानी एनएसओ के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में हमारे देश की खेती से देश की सकल घरेलू आय को मिलने वाला हिस्सा 48 फीसद से घटकर 37 फीसद रह गया है।

आज भी देश की दो-तिहाई जनता गाँवों और कस्बों में रहती है और अपने चाहता था, उसके तो पाँव उखाड़ दिए कोविड महामारी ने भारत विभाजन के पलायन जैसी त्रासदी एक बार भूख से मरने नहीं देते। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, जो अपनी अस्सी फीसद जनता को मुक्त अनाज दे रहा है, लेकिन यह दावा क्यों सामने नहीं आता कि युवा पीढ़ी जैसे ही किसी भी तरह की योग्यता हासिल करके जीवन समर में आती है, तो उसे समुचित काम देने की गारंटी नहीं मिलती। अनुदान की राहत का भरोसा मिलता है और उससे परेशान होकर किसी बेहतर जीवन को गले लगाने के लिए इस पीढ़ी के अधिकांश लोग विदेश पलायन की प्राथमिकता दे रहे हैं। इधर किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने स्वामीनाथन समिति की रपट की

सरकार तो कहती है कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देते। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, जो अपनी अस्सी फीसद जनता को मुक्त अनाज दे रहा है, लेकिन यह दावा क्यों सामने नहीं आता कि युवा पीढ़ी जैसे ही किसी भी तरह की योग्यता हासिल करके जीवन समर में आती है, तो उसे समुचित काम देने की गारंटी नहीं मिलती। अनुदान की राहत का भरोसा मिलता है और उससे परेशान होकर किसी बेहतर जीवन को गले लगाने के लिए इस पीढ़ी के अधिकांश लोग विदेश पलायन की प्राथमिकता दे रहे हैं। इधर किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने स्वामीनाथन समिति की रपट की स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया कि हम जो एमएसपी दे रहे हैं, उसमें किसान की लागत से पचास फीसद अधिक तक का फायदा है।

स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया कि हम जो एमएसपी दे रहे हैं, उसमें किसान की लागत से पचास फीसद अधिक तक का फायदा है। मगर यह लागत स्थिर रहती रही न! लागत तो स्थिर नहीं रही, महंगाई ने इसके अंजर पंजर ढीले कर दिए। आयात आधारित अर्थव्यवस्था में डालर के मुकाबले हमारी मुद्रा के अवमूल्यन ने आयातित कच्चे माल की कीमतें बहुत ऊंची कर दी। इस तरह लागत, पिछले दस वर्षों में केवल गन्ने की खेती का उदाहरण दें तो, 116 फीसद बढ़ी और उसकी कीमत बढ़ी केवल 37.2 फीसद। यही हाल बाकी फसलों का है। गेहूं, कपास, दलहन और तिलहन की कथित क्रांति का भी है। किसान तो दोगुनी आय की जगह पहले से भी गरीब हो गया।

दूसरी ओर, शहर या कस्बों में जाकर जो मज़दूर अपना पेट पालना

नियंत्रण करने के मकसद से सरकार उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। सीधा या अधिक शुल्क के रूप में। गेहूं के साथ यह घटा। बासमती चावल के बाद अब प्याज के साथ यही होने लगा है, जिसने नाशिक और महाराष्ट्र के प्याज उगाने वाले किसानों को बहुत परेशान किया है। सीधा-सा यह हल था कि गाँवों में बसती जनसंख्या को लघु और कुटीर उद्योगों की सहायता से, सहकारी अंदोलन की सहायता से व्यवसाय के वैभिन्न का उपहार दे दिया जाता। फसलों के कच्चे रूप को अंतिम रूप देने के छोटे-छोटे 'स्टार्टअप' उद्योग भी तो वहाँ लगाए जा सकते थे। गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा और गेहूं से आटा बनाने का उद्योग। मगर यहाँ तो अपनी फसल ही संभलती नहीं। इतने वर्ष हो गए, पकी फसलों का संग्रह करने के लिए उचित गोदाम

नहीं। इनके लिए दिल्ली की निर्माण होगी, जिसके बल पर हम दुनिया की

तीसरी नहीं, बल्कि अब आर्थिक दांचे का निर्माण होगा।

■ ■ ■

सुरेश सेठ

नीति नहीं बन सकी और फसलें खराब मौसम में मंडियों में जाते ही खराब हो जाती हैं। उनकी गुणवत्ता गिर जाती है और घोषित कीमतों से कम दाम पर किसान खरीद अधिकारियों की चिरोरी करता नजर आता है कि इन फसलों को खरीद लिया जाए। ऐसा मजबूर किसान क्या अनाज का भंडारी, भारत की शक्ति कहा जा सकता है ? जी नहीं। इसीलिए खेती से आय का फीसद घटा चला गया।

उधर महंगाई के इस जमाने में मंदी की आशंका ने बेकारी का फीसद घटा दिया। महंगाई ने कई रूप बदले। अजब रूप यह था कि थोक मूल्य सूचकांक तो अपनी कमी दिखा रहा था, लेकिन परचून मूल्य सूचकांक में कमी नहीं, बढ़त दिखाई दे रही थी। जाहिर है यह कालाबाजारियों और बनावटी मंदी पैदा करने वालों की कृपा थी, लेकिन मरा तो वह साधारण आदमी, जिसे पहले निर्धन कहा जाता था, आजकल निम्न मध्यवर्गीय कहा जाता है। ऐसी हालत में कैसे हम कह दें कि जो आर्थिक तरक्की देश को मिली है, उसने हमारा सिर दुनिया में ऊंचा कर दिया। शिक्षा की नई नीति बनी, जिसमें अब इंटरनेट की जानकारी की क्षमता वाले लोग ही युगानुरूप हैं, और एक बड़ी आबादी असंबद्ध हो गई। बेशक इसके हल के लिए इस स्वाधीनता दिवस पर विश्वकर्मा योजना घोषित की गई है, जिसमें रोहिणी आयोग की रपट के अनुसार उन जातियों और विरादरियों को लाभ मिलेगा जैसे बढ़ी, लुहार और दूसरी कामगार जातियां, जो मूल निर्माण करती हैं। इनके प्रशिक्षण की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज उनके प्रशिक्षण की बात होने लगी है, लेकिन यह पहल कितनी सार्थक होगी, देखने की बात है। यह विश्वकर्मा योजना उनके लिए कितनी सार्थक होगी, इसी बात पर देश के उस मूलभूत आर्थिक ढांचे का निर्माण होगा, जिसके बल पर हम दुनिया की तीसरी नहीं, बल्कि अब अवल आर्थिक शक्ति बन सकेंगे।

केजरीवाल सरकार जी-20 की तर्ज पर चमकाएगी पूरी दिल्ली

केजरीवाल सरकार जी-20 के तर्ज पर अब पूरी दिल्ली को खूबसूरत बनाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी का ग्राउंड जीरों पर निरीक्षण जारी है। मंत्री ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ सेंट्रल दिल्ली में शंकर रोड व पूसा रोड का निरीक्षण किया व उन्हें सड़कों को रिडिजाइन कर स्वच्छ, सुंदर और यूजर फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादा किया है कि जैसे जी-20 के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों को

साइबर अपराध का बढ़ता ख़तरा

विनोद के शाह

पिछले तीन वर्षों में देश के बैंकिंग आर्थिक साइबर अपराधों में करीब तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में ठगी गई रकम की मात्रा में पांच गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। वर्ष 2021 में देश में दर्ज साइबर ठगी के मामलों की संख्या 7.05 लाख थी, जो मार्च 2023 तक 19.94 लाख पर पहुंच चुकी है। इस अवधि में ठगी गई राशि वर्ष 2021 के 542.7 करोड़ रुपए के मुकाबले मार्च 2023 में 2537.35 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साइबर अपराधों में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए गठित संसदीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से सिफारिश की है कि वह पीड़ित ग्राहकों को मुआवजा देने का सरल प्रावधान बनाए। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए साइबर सुरक्षा प्राधिकार की स्थापना, फोन पर कर्ज़ देने वाली वित्तीय समितियों और काली सूची में शामिल लोन एजेंसियों की सूची का अलग-अलग सार्वजनिक प्रकाशन करने की सिफारिश भी संसदीय समिति ने आरबीआइ से की है।

वर्ष 2022-23 में बैंकों ने 8.5 करोड़ नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड से व्यापार में 42 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है। बैंकों की आय में भी ज़बरदस्त उछाल आया है। मगर इसके विपरीत क्रेडिट कार्ड से होने वाली ठगी पर रोक लगाने के उपाय खोजने में बैंक विफल साबित हो रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्तमंत्री ने स्वीकार किया कि एक साल में क्रेडिट कार्ड का एनपीए 28 फीसद की दर से बढ़ कर 2.10 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। बैंक अधिक कमाई और ब्याज वसूली के लिए अधिक से अधिक क्रेडिट कार्ड ग्राहक बनाने के मिशन में जुटे हैं, मगर क्रेडिट कार्ड को अपराधियों से सुरक्षित बनाने

में गंभीर नहीं हैं। हाल में देश के राष्ट्रीयकृत बैंक आफ बड़ौदा में मप्र और दिल्ली के उन ग्राहकों के साथ बड़ी संख्या में धोखाधड़ी हुई, जो डिजिटल सेवा से जुड़े नहीं थे। शिकार ग्राहकों ने न कभी बैंक से एटीएम लिया, न ही ओटीपी साझा किया था। ग्राहकों से अनुमति लिए बैंक बैंक ने सभी ग्राहक खातों को बैंक के एक ऐप से जोड़ दिया था, जो ग्राहकों की ठगी का कारण बना। बैंक की गलती के बावजूद पीड़ित ग्राहकों के खाते में राशि नहीं लौटाई गई है।

बैंकिंग विनियम में यूपीआइ को सुरक्षित बताकर अधिक लोकप्रिय बनाया जा रहा है। छिह्नतर फीसद लेनदेन अब यूपीआइ के माध्यम से होने लगा है। मगर इस सेवा में ग्राहक हित सुरक्षा को शून्य रखा गया है। सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत क्षति प्राप्ति के दायरे में नहीं आता है। यह अपनी क्षतिपूर्ति का प्रकरण उपभोक्ता विवाद आयोग में पेश करने की पात्रता नहीं रखता है। क्योंकि सेवाग्राहिता सेवा के बदले वह सेवा प्रदाता कंपनी को किसी राशि का भुगतान नहीं करता है। इसलिए उपभोक्ता आयोग उसे ग्राहक नहीं मानता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में यूपीआइ से होने वाले लेनदेन पर कंपनियों को सेवाकर लेने की सिफारिश केंद्र सरकार से इसी वजह से की थी। मगर सरकार ने विचार करने के लिए सिर्फ पैसे से जुड़े गेम पर जीएसटी की दर को 18 फीसद से बढ़ा कर 28 फीसद कर इस जानलेवा आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का उपाय खोज रही है। इन कंपनियों पर पहले से ही 58 हजार करोड़ रुपए का आयकर और 30 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। संगठित गेमिंग कंपनियां जोर-शोर से इसे भारत की चालीस करोड़ जनता को मनोरंजन देने वाली औद्योगिक इकाई बता कर केंद्र की स्टार्टअप योजना में संरक्षण पाने का दावा भी कर रही हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में जुआ, सद्गुण, लाटी और आनलाइन गेम को राज्य का विषय बताकर उसे नियंत्रित की मिलीभगत से संभव हो पा रहे हैं।

‘केवाइसी’ कराने के नाम पर बैंक, बीमा कंपनियां, मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां, शिक्षा और कोचिंग संस्थान समय-समय पर अपने ग्राहकों से ‘केवाइसी’ दस्तावेज लेने के बाद उनका सुरक्षित भंडारण और निष्पादन नहीं करते हैं। एक रपट के अनुसार जनवरी से मार्च 2023 की तीन माह की अवधि में देश के इक्कीस लाख बैंक खातों से डेटा चोरी हुआ। देश के बैंकों पर साइबर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके, बैंक साइबर सुरक्षा पर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2023’ के माध्यम से डेटा सुरक्षित करने का एलान जरूर किया है, लेकिन इसमें अनेक विसंगतियां हैं।

देश में नकली वेबसाइटें, मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम और लोन ऐप सिर्फ आर्थिक उगी नहीं, इंसानी जिंदगियों को मौत में बदलने और धर्मात्मरण जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं। मोबाइल गेम के कारण देश के सैकड़ों किशोर आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मगर केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए सिर्फ पैसे से जुड़े गेम पर जीएसटी की दर को 18 फीसद से बढ़ा कर 28 फीसद कर इस जानलेवा आपराधिक गतिविधि को नियंत्रित करने का उपाय खोज रही है। इन कंपनियों पर पहले से ही 58 हजार करोड़ रुपए का आयकर और 30 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। संगठित गेमिंग कंपनियां जोर-शोर से इसे भारत की चालीस करोड़ जनता को मनोरंजन देने वाली औद्योगिक इकाई बता कर केंद्र की स्टार्टअप योजना में संरक्षण पाने का दावा भी कर रही हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में जुआ, सद्गुण, लाटी और आनलाइन गेम को राज्य का विषय बताकर उसे नियंत्रित करने की विशेष बताकर उसे नियंत्रित करने की अपेक्षा कर रही है।

करने की व्यवस्था राज्य पुलिस के अधीन की गई है। अपराधी आनलाइन लाटरी, मोबाइल गेम को अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय स्थलों से संचालित कर रहे हैं, जहां राज्य पुलिस की आसान पहुंच ही संभव नहीं होती है। पूरे देश में श्साइबर ब्लैकमेलिंग, हत्या और आत्महत्या के सैकड़ों किसी एक ही प्रकार से हैं, जिनका मूल आनलाइन कर्ज, गेम और लाटरी से जुड़ा है। पहले मोबाइल के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो बैंक किसी दस्तावेज के बिना दिन की अवधि । केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2023’ के माध्यम से डेटा सुरक्षित करने का एलान जरूर किया है, लेकिन इसमें अनेक विसंगतियां हैं।

साइबर अपराधी इतने शातिर और अत्यधिनियम तकनीक से लैस हैं कि राज्यों की पुलिस पांच फीसद आरोपियों को मौत में बदलने और धर्मात्मरण जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं। मोबाइल गेम के कारण देश के सैकड़ों किशोर आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मगर केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए सिर्फ पैसे से जुड़े गेम पर जीएसटी की दर को 18 फीसद से बढ़ा कर 28 फीसद कर इस जानलेवा आपराधिक गतिविधि को नियंत्रित करने का उपाय खोज रही है। इन कंपनियों पर पहले से ही 58 हजार करोड़ रुपए का आयकर और 30 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। संगठित गेमिंग कंपनियां जोर-शोर से इसे भारत की चालीस करोड़ जनता को मनोरंजन देने वाली औद्योगिक इकाई बता कर केंद्र की स्टार्टअप योजना में संरक्षण पाने का दावा भी कर रही हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में जुआ, सद्गुण, लाटी और आनलाइन गेम को राज्य का विषय बताकर उसे नियंत्रित करने की अपेक्षा कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्वेश पर केंद्र सरकार ने 2020-21 में चीन से संचालित होने वाले डेटा सौ मोबाइल ऐप पर रोक लगाई थी। मगर उनमें से अधिकांश ऐप फिर नाम बदल कर संचालित हो रहे हैं। देश में साइबर अपराधी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मगर देश अब भी संविधान की सातवीं अनुसूची का हवाला देकर राज्यों की पुलिस से अपराध को ख़त्म करने की अपेक्षा कर रहा है।

ख़ास ख़बरें

अमरीकी सैनिक को रिहा करेगा उत्तर कोरिया

सियोल : उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने जुलाई में भारी हथियारों से लैस अंतर- कोरियाई सीमा से देश में प्रवेश करने वाले एक अमरीकी सैनिक को रिहा करने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि अधिकारियों ने पकड़े गए अमरीकी सैनिक ट्राविस किंग से पूछताछ पूरी कर ली हैं। इसने दावा किया कि सैनिक ने स्वीकार किया है कि उसने अवैध रूप से उत्तर कोरिया में प्रवेश किया क्योंकि वह अमरीकी सेना के भीतर अमानवीय दुर्व्यवहार और नस्तीय भेदभाव के सिलाफ था।

मणिपुर : अनेक ज़िलों में अभी भी अशांत

मणिपुर में मैत्री छात्रा-छात्रा के अपहरण और हत्या के खुलासे के बाद मणिपुर फिर अशांत हो गया है। इंसाफ की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दो दिन स्कूल बंद रखने की घोषणा के बावजूद छात्र सङ्कालन भी जारी रहा। इम्फाल में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इम्फाल में सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लोकलाओवंग में इम्फाल ईस्ट के एसडीओपी की गाड़ी जला दी गई। थाउबल में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा का मंडल कार्यालय फूंक दिया और 5,000 से अधिक युवाओं ने डीसी कार्यालय की तरफ धावा बोला। दो दिन के प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से 14 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं।

मुखर्जी नगर : गर्ल्स हास्टल में आग लगी, छात्राओं को बचाया

दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल में आग लगने से अफरातरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना मिलने पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर घटनास्थल पहुंची। दमकल कर्मियों ने कुलिंग अभियान के तहत आग पर काबू पाने के प्रयास किए। दमकल अधिकारियों ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी, उसमें कुछ लड़कियों की फंसे होने की सूचना मिली। इमारत में फंसी 35 लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला गया।

ट्रैप ने रियल एस्टेट कारोबार में की धोखाधड़ी : जज

न्यूयार्क : पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रैप के खिलाफ एक न्यायाधीश फैसले में कहा कि ट्रैप ने रियल एस्टेट कारोबार खड़ा करते समय बरसों बरस धोखाधड़ी की, जबकि इसी कारोबार ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और व्हाइट हाउस तक पहुंचाया। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटीशिया जेम्स द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आर्थर एंगोरेन ने ट्रैप के खिलाफ अपनी व्यवस्था में यह कहा।

उज्जैन में 12 साल की नाबालिग से दरिंदगी के मामले में आटो ड्राइवर गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची से दरिं

इस्लामियत

हलाल दोज़ी की अहमियत

रसूल अकरम सल्ललाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 'मैं तुम्हारे दर्मियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह यानि कुरआन करीम और दूसरी सुन्नते रसूल सल्ललाहो अलैहि वसल्लम। जब तक तुम इन्हें मज़बूती के साथ पकड़े रहोगे, तुम हरागिज़ गुमराह नहीं होंगे। (बुखारी शरीफ) इस संक्षिप्त और व्यापक हिदायत में आप सल्ललाहो अलैहि वसल्लम ने कुरआन करीम और सुन्नत रसूल की अहमियत बता दी और उमरभर के लिये ज़िन्दगी का उसूल बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई इन से ग़फ़्लत करता है तो उसका कुसूर है। मज़बूती से पकड़ने का मतलब है कि उसकी तिलावत करना, उसके अर्थ और मतलब को समझना और इस पर अमल करना। यह हुक्म हर मुसलमान मर्द, औरत के लिये है।

इस्लाम धर्म की यह ख़ूबी है कि क़्यामत तक पेश आने वाले हालात की रोशनी में इंसान की रहनुमाई की गई है। ज़िंदगी का कोई गोशा तिश्ना नहीं रखा गया है। कुरआन करीम को अध्ययन करने वालों पर भी यह बात ज़ाहिर है इसी तरह हदीसों का अध्ययन करने वालों पर भी यह बात स्पष्ट है कि उनके ज़रिए इंसान की मुकम्मल रहनुमाई की गई है। लगभग साढ़े चौदह सौ वर्ष पहले रसूल मक़बूल सल्ललाहो अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वह आज के हालात के बिल्कुल मुताबिक है। यह महसूस ही नहीं होता है कि यह शताब्दियों पहले की बात है। सच है अगर इल्मे नबुव्वत और अल्लाह की वह्य से हमारी रहनुमाई नहीं की जाती तो सब भटकते ही रह जाते और असल मंज़िल तक न पहुंच पाते क्योंकि इंसानी संसाधन से हासिलशुदा इल्म में ग़लती का इमकान (संभावना) रही है, इसके ज़रिये इंसान को जो इल्म हासिल होता है उसमें हर हाल में ग़लती की संभावना होती है। अक़ल गलती कर देती है और कर सकती है। विजदान व कश्फ में भी सकम हो सकता है जबकि इंसान ऐसे निर्णयिक व क़र्तई इल्म की तलाश रखता है जिसमें ग़लती और ख़तरा की मामूली सी भी संभावना मौजूद न हो। यह बहुत मुमकिन है कि ज़ैद की आंख ने जो कुछ देखा है बक्र की आंख उसे ग़लत साबित कर दे। एक शख्स की अकल एक दलील से जो नीतीजा निकाले दूसरे की सोच उसी दलील से उसके विपरीत परिणाम पेश कर दे, इसी तरह विजदान और दूसरे हवास के फैसलों में ग़लती की संभावना

रहती है, लेकिन इल्म का वह दर्जा कमाल और इल्म की वह बुलंद हालत जहां गलती और ख़तरा का कोई इमकान ही न हो, जिस में शक व शुब्द की गुंजाइश ही न हो, वह सिर्फ और सिर्फ बारगाहे नबुव्वत व रिसालत से ही हासिल हो सकती है या फिर उन अल्लाह वाले के फैज़ाने नज़र से जो अपनी ज़ात को अनवारे नबुव्वत व रिसालत से रोशन कर चुके हैं, इमाम ग़ज़ाली रह। फरमाते हैं कि इंसानी हवास हों या इंसानी अक़ल, यह सारे के सारे संसाधन इंसान को निश्चित इल्म उपलब्ध नहीं कर सकते, यक़ीनी इल्म केवल उसे हासिल होता है जो आफताबे नबुव्वत के अनवार से अपने सीने को रोशन कर रहा हो और यह मकाम सूफिया को नसीब होता है (अल मुनाकिज़ मिनज़लाल पृष्ठ-509, ईमान बिर्रिसालत पृष्ठ-32)। मिसाल के तौर पर जायज़ और नाजायज़ आमदनी और हराम चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसकी इबादत कुबूल नहीं होती है और दुआ भी कुबूल नहीं होती इसलिये हर एक को यह कोशिश करनी चाहिए कि हलाल आमदनी हो और इसमें नाजायज़ आमदनी की बिल्कुल मिलावट न हो। बाज़ चीज़ें संदिग्ध (मुश्तबेह) होती हैं जिन के बारे में संदेह होता है कि यह हलाल है या हराम। इनके बारे में रसूल सल्ललाहो अलैहि वसल्लम ने दो टूक शब्दों में इस तरह बयान फरमाया "हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहो अन्हों से रिवायत है कि रसूल सल्ललाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल चीज़ें ज़ाहिर हैं और हराम ज़ाहिर हैं और इन दोनों के दर्मियान संदेह वाली चीज़ें हैं जिनकी हकीकत से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं तो जो शख्स शुब्द की चीज़ों से बचा, उस ने अपना दीन पाक कर लिया और अपनी आबूर्द को महफूज़ कर लिया और जो शख्स संदेह (शुब्द) की चीज़ों में लिप्त हो वह हराम में लिप्त हुआ, उसकी कैफियत उस चरवाहे के समान है जो खेत के मुंडेर के पास अपने जानवर को चराए और हर बक्त इसका ख़तरा रहे कि कोई जानवर खेत में न घुस जाए। ख़बरदार हो जाओ। हर बादशाह की एक हद मुकर्रर है और ख़ुदा की हद हराम चीज़े हैं। आगाह हो जाओ कि इंसान के शरीर में एक गोश्त का टुकड़ा है जब यह ठीक रहता है तो पूरा बदन ठीक रहता है और जब वह ख़राब हो जाता है तो पूरा बदन ख़राब हो जाता है और वह दिल है (बुखारी व मुस्लिम) हर इंसान की जिस्मानी तंदुरुस्ती की भी बुनियाद दिल पर होती है और रुहानी तंदुरुस्ती की बुनियाद भी दिल होता है। बेहतर तंदुरुस्ती बरक़रार रखने के लिये ज़रूरी है कि खाने पीने में विशेष सावधानी बरती जाए। माहिर डॉक्टरों और हकीमों की सलाह और मश्वरे पर

ये लोग तुमको दोजख की ओर बुलाते हैं।

अर्थात् मुश्विरिक मर्द और औरतें जिनका वर्णन हुआ है उनके साथ बातचीत, अनेक कार्य उनसे प्रेम उनके साथ रहना सहना शिर्क की बुराई को दिल से कम कर देता है और सिर्फ की ओर आकर्षण का कारण बनता है, जिसका परिणाम दोजख है। ऐसों के साथ विवाह करने से बचना चाहिए। रुकूं न। 27

और अल्लाह जन्नत की ओर तथा सभा की ओर अपने आदेश से बुलाता है। और अल्लाह अपने आदेश लोगों को बतलाता है ताकि वे उपदेश प्राप्त करें और ये लोग आप से हैज (मासिक धर्म) के सम्बन्ध में पूछते हैं आप कह दीजिए कि वह गन्दी वस्तु है। सो तुम हैज के समय अपनी औरतों से दूर रहो।

हैज उस खून को कहते हैं जो स्त्रियों को स्वभाविक रूप से आता है। हैज की दशा में सम्भोग करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना सब हराम है और स्वभाविकता के विपरीत जो खून जाता है यह बीमारी है उसमें सम्भोग करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना सब उचित है। उसकी दशा ऐसी ही है जैसे घाव का खून बहने की यहूदी हैज की दशा में औरत के साथ खाने और एक घर में रहने को भी ठीक न समझते थे और ईसाई सम्भोग से भी नहीं रुकते थे। ह मुहम्मद स। से पूछा गया तो उस पर यह जायत उतरी। आपने स्पष्ट कह दिया कि उस दशा में सम्भोग हराम है। उनके साथ खाना पीना रहना सहना ठीक है। यहूदियों का सीमा से अधिक बढ़ना और ईसाइयों का बिल्कुल इस दशा को न मानना दोनों का खन्डन हो गया।

और उनके पास न लगो जब तक वे पाक न हो जायें।

पाक होने का अर्थ यह है कि यदि अपने समय की सीमा अर्थात् दस दिन पर समाप्त हो तो समाप्ति के समय से ही सम्भोग ठीक है और यदि दस दिन से पहले जैसे छः दिन के पश्चात् समाप्त हो गया और स्त्री का स्वभाव भी छः दिन का है तो खून के समाप्त होते ही सम्भोग ठीक नहीं पहले औरत स्नान करें या नमाज का समय बीत जाये उसके सम्भोग ठीक होगा। अगर स्त्री की आदत सात आठ दिन की थी हो उन दिनों के पश्चात् ही सम्भोग ठीक होगा। फिर जब भली-भाँति पाक हो जायें तो उनके पास जाओ जाओ। जहां से तुम को अस्लाह ने आज्ञा दी है।

जिस स्थान से सम्भोग की स्वीकृति दी है रास्ते से जड़ों से बच्चा पैदा होता है। दूसरे स्थान अर्थात् पीछे से जहां से टट्टी होती है सम्भोग करना हराम है।

निःसन्देह अल्लाह तौबा करने वालों से मुहब्बत करता है और गन्दी से बचने वालों से भी।

अर्थात् जो तौबा करते हैं गुनाह से, जो उनसे अनजानेपन में हो गया, जैसे हैज में संभोग और अपवित्रता अर्थात् टट्टी के मार्ग से या हैज के समय संभोग से बचते हैं।

अमल किया जाए, हर मुसलमान के हिदायत का एहसास भी नहीं होता। वह शरीर अत की ख़िलाफ़वर्जी करता ही रहता है। आजकल बीमा की नई नई स्कीमें निकल चुकी हैं। बैंक के लोन और कर्ज मिलने के नये-नये तरीके मौजूद हैं। इसमें सूद का कारोबार है। रूपये में इजाफ़े के लिये एक और बहुत से तरीके हैं। बोली वाली लॉटरी का रिवाज़ पड़ गया है। किसी का पैसा लेकर वापस न करना, ज़मीन दबा लेना, हक़ तल्फ़ी (अधिकार हनन) करना आम बात हो गई है। वारिसों को हक़ देने में आना कानी, लड़कियों के अधिकार देने में लापरवाही और ग़फ़्लत, यतीमों और बेवाओं के अधिकारों की पामाली यह सब बातें इंसान अपना पैसा बढ़ाने के लिये करता है अगर दूसरा पक्ष बेबस होकर चुप भी हो जाए तो यह पैसा जायज़ नहीं हो जाता। तिजारत में बेईमानी, झूठ और गलतबयानी भी कर्माई को नाजायज़ बना देती है। ऐसे ही मौके पर शरीर अत की पाबंदी करना सवाब है, इससे ईमान भी सलामत रहता है और ख़ैर व बर्कत भी होती है।

तमिलनाडु-द्रमुक के हिंदी प्रेम का मतलब

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने हाल ही में हिंदी में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्रिवटर) पर एक पोस्ट डालकर सबको चौका दिया है। इससे न केवल हिंदी विरोधियों कोश झटका लगा, बल्कि हिंदी प्रेमी भी इससे खुश हैं और इसे स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। वर्ष 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर सुख्खियों में रही द्रमुक ने अचानक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से किए गए पोस्ट में लिखा है कि 'जब तक महिलाओं की यह मासिक अनुदान मिलता है, इसका मतलब है कि स्टालिन इस भूमि पर (तमिलनाडु में) शासन करता है'।

क्या यह द्रमुक द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों से उठे व्यापक विवाद के बाद पार्टी द्वारा सोची-समझी गई रणनीति के तहत उठाया गया कदम है? अचानका पार्टी के रुख में आए इस बदलाव का कारण क्या है? इस ट्रीट के समय को देखते हुए समझय जा सकता है कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर जो विवादास्पद टिप्पणियां की, उससे न सिर्फ द्रमुक, बल्कि विपक्षी, दलों का नवगठित गठबंधन और उसी से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। यह ट्रीट इसलिए जरूरी स्टालिन को लगा कि उनका वन लाइनर बयान तीखा हो गया था?

गैरतत्त्व है कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने अन्नादुरई के जन्मदिन पर एक लोकप्रिय सामाजिक कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बयान दिया था। द्रमुक को मुख्यमंत्री स्टालिन का वन लाइनर और तमिल में एक वीडियो पोस्ट करने की अचानक जल्दबाजी क्यों है? तमिलनाडु के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि द्रमुक ने ख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि द्वारा उठाए गए सनातन धर्म विवाद र आम लोगों एवं राजनीतिक पार्टियों के गुस्से को कम करने के लिए हिंदी में पोस्ट डाली।

पिछले दो महीने से तमिलनाडु सरकार व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले हिंदी दैनिक अखबारों में हिंदी विज्ञापन प्रकाशित करवा रही है। इसके अलावा, द्रमुक ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी हिंदी सामग्री पोस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या यह द्रमुक द्वारा उत्तर भारतीयों के करीब जाने की कोशिश है, ताकि

यदि विपक्षी इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता में आए, तो उसे पर्याप्त महत्व मिले? क्या इसका मतलब यह भी है कि द्रमुक हिंदी पर अपने रुख से समझौता करेगी संयोग से यह पोस्ट द्रमुक द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर अपलोड किया गया था। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा लोकप्रिय रूप से हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तमिलनाडु में विपक्षी दल है, लेकिन उसने भी द्रमुक द्वारा हिंदी में पोस्ट किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि हृदय परिवर्तन

का हमेशा स्वागत है। गैरतत्त्व है कि 2019 के हिंदी दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान पर कि हिंदी देश में सबसे अधिक पढ़ी और समझी जाने वाली भाषा है, स्टालिन ने जवाबी हमला बोला था कि यह 'इंडिया है, हिंदिया नहीं। एमके स्टालिन के पिता और द्रमुक के संस्थापक करुणानिधि का हिंदी विरोध तो जगजाहिर ही था। उन्होंने गैरहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए हिंदी का विरोध किया था। लेकिन अब जबकि द्रमुक हिंदी में पोस्ट कर रही है, तो तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी भाजपा आश्चर्यजनक

रूप से इसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखकर स्वागत कर रही है। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया कि इस तरह के हृदय परिवर्तन का हमेशा स्वागत है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बयान जारी कर सनातन धर्म विवाद पर भी यूटर्न ले लिया है। उनका कहना है कि भाजपा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) घोटाले को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से जनता का ध्यान भटका रही है। स्टालिन ने अपने प्रवक्ता को सलाह दी कि वह शसनातन में न आएं। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को भाजपा के भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, दूसरी तरफ कोर्वई सत्यन जैसे अन्नाद्रमुक के नेताओं ने टिप्पणी की कि द्रमुक अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे से बाहर निकलने की हताश कोशिश कर रही है। इसीलिए द्रमुक अचानक हिंदी में पोस्ट करने लगी है। अन्नाद्रमुक समेत विपक्षी दलों ने ओणम पर केरलवासियों के लिए मलयालम में शुभकामना वीडियो जारी करने के लिए भी स्टालिन का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर वह हिंदी में पोस्ट कर सकते हैं, तो गणेश चतुर्थी या दिवाली या रामनवमी पर उत्तर भारतीयों को शुभकामनाएं क्यों नहीं दे सकते? इससे पहले भी अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और पनीरसेल्वम ने हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार के दोहरे मानकों को लेकर हमला बोला था।

ढाई करोड़ मतदाताओं के इर्द गिर्द धूमता मध्य प्रदेश का चुनाव

मनोज मनु

अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता देना।

अगर किसी इलाके की महिला नहीं चाहेगी तो वहां पर शराब की दुकान नहीं खोलना इसके लिए नीति में परिवर्तन किया जाएगा।

गांव में निशुल्क भूखंड और शहरों में अतिक्रमण से मुक्त जमीनों पर भूखंड बहनों को दिए जाएंगे।

सितंबर तक बड़े हुए बिजली बिलों की वसूली नहीं होगी।

मजनू टोलों में जिनके घर बिजली के नहीं हैं वहां 20 घर की बस्ती में भी पूरी बिजली दी जाएगी।

लाडली बहनों की फीस भरी जाएगी। उद्योगों के लिए महिलाओं का विजली बिल 100 रुपए में सिलेंडर, एक घर के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट तक बिजली माफ, किसानों का कर्ज माफ, किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर की सिंचाई पंप के लिए स्थाई और अस्थाई कनेक्शन पर फ्री बिजली, 12 घंटे। व सिंचाई के लिए बिजली, पुराने बिजली हो बिल माफ और किसानों के मुकदमे वापस करने। इसके साथ ही जो पुराना वादा जिसमें पुरानी पेंशन देने का वादा की भी किया गया है और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की बात भी इन वचनों में की गई।

पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण। शिक्षकों के पदों में 50 प्रति। महिलाओं की नियुक्ति करना। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन और कार्यकारी संपादक हैं।

द्रमुक के हिंदी पोस्ट को लेकर लोगों का नजरिया चाहे जो भी हो, यह -पार्टी के नजरिये में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है, जिसका हिंदीष मट्टी के लोग व्यापक रूप से स्वागत कर सकते हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या स्टालिन और उनकी पार्टी बांगला, उड़िया, गुजराती, मराठी और असमिया भाषियों तक इसी तरह की पहुंच बनाएंगी।

खेल जगत

सुमित नागल बोले - मैं टटरहा हूं मेरे खाते में सिफ 80 हजार रुपए बचे हैं

भारत के नंबर- 1 टेनिस स्टार सुमित नागल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एटीपी टूर में खेलने के लिए एक करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था करने के बाद नागल के बैंक खाते में लगभग 80 हजार रुपए (900 यूरो) ही बचे हैं और वे अच्छी जिंदगी नहीं जी पाने के कारण निराश हैं। सुमित नागल एटीपी सिंगल रैंकिंग में 159वें स्थान पर हैं, जो भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ है। नागल ने न्यूज एंजेंसी च्यू से बातचीत में अपना दर्द बया किया। नागल को एटीपी टूर में खेलने के लिए एक करोड़ रुपए देने थे। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी पुरस्कार राशि, आईओसीएल से मिलने वाला अपना वेतन और महा टेनिस फाउंडेशन से मिलने वाली सहायता राशि को खर्च किया। खिलाड़ियों का यह खर्च प्रैक्टिस सेंटर में रुकने और अपने कोच या फिजियो के साथ टूनामेंट के लिए यात्राओं पर होता है। राशि जमा करने के बाद नागल अपना और अपने परिवार का खर्च तक नहीं चला पा रहे हैं। नागल पिछले कुछ वर्षों से

जर्मनी की नानसेल टेनिस अकादमी में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे 2023 के सत्र

के शुरुआती तीन महीनों में अपने पसंदीदा स्थान पर अभ्यास नहीं कर पाए। उनके मित्र सोमदेव देववर्मन

और क्रिस्टोफर मार्कुइस ने जनवरी के फरवरी में उनकी मदद की थी। नागल ने कहा कि अगर मैं अपने

बैंक में जमा धनराशि की बात करूं तो मेरे पास इतनी ही राशि है, जितनी की वर्ष के शुरुआत में थी। नागल ने कहा कि अगर मैं अपने बैंक में जमा धनराशि की बात करूं तो मेरे पास इतनी ही राशि है, जितनी की वर्ष के शुरुआत में थी। यह 900 यूरो (लगभग 80,000 रुपए) है। मुझे थोड़ी मदद भी मिली। महा टेनिस फाउंडेशन के प्रशांत सुतार मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे आईओसीएल से मासिक (वेतन) भी मिलता है, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा प्रायोजक नहीं है। नागल ने इस साल 24 टूनामेंट में हिस्सा लिया, जिनसे उन्होंने लगभग 65 लाख रुपए की कमाई की। उन्हें सबसे बड़ी पुरस्कार राशि अमेरिकी ओपन से मिली जहां वह क्वालिफायर के पहले दौर में हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 22000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 18 लाख रुपए) मिले। उन्होंने कहा- मैं जो भी कमाई कर रहा हूं उसे खर्च कर दे रहा हूं। मेरा वार्षिक खर्च लगभग 80 लाख से लेकर

बाकी पेज 11 पर

पाकिस्तान का 'हैरी पॉटर' बदलेगा अब अपनी टीम की तक़दीर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अब अपने बेस्ट स्पिनर को उतारने का मन बना चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में हैरतअंगेज प्रदर्शन करने वाले लेग स्पिनर अबरार अहमद पर टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के बीच राय बनती दिख रही है। ये वही अबगर हैं जिन्होंने छह टेस्ट में 38 विकेट लेकर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने शानदार प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान टीम के साथ दिक्कत यह है कि उसके लेगस्पिन ऑलराउंडर और उपकप्तान शादाब खान गेंदबाजी में अपनी फॉर्म पूरी तरह खो चुके हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और अब एशिया कप में वह बेहद औसत दर्जे के गेंदबाज साबित हुए। यहां तक कि अब उनकी काफी गेंदें शॉट पड़ने लगी हैं। रही सही कसर उनकी

ओवरपिच और फुलटॉस गेंदों ने पूरी कर दी है। कहा यह जाता है कि वह बल्लेबाजी पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उनकी बढ़िया बल्लेबाजी भी अरसे से देखने को नहीं मिली। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान क्यों न अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर को उनकी जगह खिलाए लेकिन खबर है कि शादाब भी टीम में रहेंगे और अवसर भी। तीसरे लेग स्पिनर उसामा मीर को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए कि वह भी हमारे चहल की तरह बल्लेबाजी करना नहीं जानते। अब अबरार और उसामा में से कोई एक ही रह सकता है और अबरार की हालिया रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियां उन्हें कही ऊपर रखती हैं। अबरार मॉर्डन डे क्रिकेट के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं। बेशक उन्होंने अभी तक एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला है लेकिन उनकी गेंदबाजी

दमदार है। उन्हें पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। उनका जोर लेंग्थ बॉल पर रहता है। फुल लेंग्थ की गेंदों का इस्तेमाल वह एक अचूक हथियार की तरह करते हैं और उसमें भी उनका जोर खासकर ऐसी गेंदों पर पुछला बल्लेबाजों को निपटाना होता है। इतना ही नहीं, उन पर स्वीप या रिवर्स स्वीप खेलना खतरे से खाली नहीं है। स्वीप का मास्टर जो रुट भी उनके सामने ऐसा ही शॉट लगाते हुए आउट हुआ था।। इतना ही नहीं, बैन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, जैक काले और न्यूजीलैंड के टॉम लॉथम और डेरेल मिचेल भी उन पर स्वीप या रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए। अबरार की स्टॉक बॉल में ज्यादा टर्न नहीं है जबकि उनकी गुगली में ज्यादा टर्न है जिस पर वह बेन स्टोक्स

बाकी पेज 11 पर

बाकी पेज 11 पर

स्वास्थ्य

अच्छी सेहत के लिए बैठेन रहिए

तकनीक ने कार्य संस्कृति को काफी बदल दिया है। ज्यादातर क्षेत्रों में कार्य शैली डिजिटल रूप ले चुकी है। ऐसे में घर से ही काम करने की सहूलियत होने पर देर तक बैठे रहने की गुंजाइश और अधिक बढ़ गई है। शोध और एक्सपर्ट बताते हैं कि शारीरिक निष्क्रियता बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। हर साल 53 लाख लोगों की मृत्यु शारीरिक निष्क्रियता के कारण हो जाती है। लगातार 8-10 घंटे कूर्सी पर बैठे रहने से न सिर्फ मांसपेशी और हड्डी कमजोर हो रही है, शरीर के विभिन्न अंगों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहना, हृदय तंत्र के साथ साथ पाचन रोगों का शिकार बना रहा है।

हो रही हैं ये समस्याएं

बवासीर : सूडान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस के अनुसार, 15 घंटे से अधिक समय तक लगातार बैठकर काम करते रहने से पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण पर कम गौर किया जाता है, पर अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आपकी चलने-फिरने की गतिविधियां कम हैं तो ये बवासीर का कारण बन सकता है। नियमित व्यायाम और समय-समय पर सीट से उठते रहना जरूरी है। पीठ दर्द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हेल्थ एजुकेशन डिविजन ने

लंबे समय तक डेस्क जॉब करने वाले लोगों का अध्ययन किया है। इसके अनुसार, लंबे समय तक बैठे रहना पीठ दर्द का कारण बन जाता है। इससे पीठ, गर्दन, हाथ और पैरों का तनाव बढ़ सकता है। खासकर, बैठने की सही व्यवस्था न होना, गलत पॉस्चर, पीठ की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी की डिस्क पर दबाव डालते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो सकती है। यहां तक कि लंबे समय तक बिना मूवमेंट कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते रहना गर्दन व कंधे के जोड़ों में तेज दर्द का कारण बन जाता है। य डायबिटीज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध बताते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर का मेटाबोलिज्म प्रभावित हो सकता है। इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और टाइप-2 डायबिटीज होने का जोखिम कई गुना बढ़ सकता है। मांसपेशियां शिथिल होने पर खून से ग्लूकोज ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है।

मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवार्नमेंट रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ की स्टडी के अनुसार, 5 घंटे से अधिक समय तक बैठे रहने पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियां कमजोर होने से चलने व संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती हैं।

काम आएंगे ये व्यायाम
लंबे समय तक बैठने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक सप्ताह व्यक्ति कम से कम 150 मिनट व्यायाम करे। मांसपेशियों को लचीला

लगते हैं। इसके कारण चलने-फिरने में दर्द होता है और शरीर का संतुलन भी प्रभावित होता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द और घुटने में स्टिफनेस, पिंडली व टखने के आसपास के हिस्सों में सूजन आ सकती है। वजन बढ़ना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवार्नमेंट रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के अनुसार व्यायाम से परे रोजमर्झ की गतिविधियां जैसे खड़े होना, चलना, तेजी से चलना, किसी भी रूप में हिलने-डुलने पर कैलारी की खपत होती है। ऊर्जा की यह खपत गैर व्यायाम गतिविधि या थर्मोजेनेसिस कहलाती है। इसकी कमी से वजन बढ़ने लगता है। इनके अलावा लंबे समय तक बैठने से हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायरॉइड हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। इन अंगों पर पड़ता है ज्यादा असर लंबे समय तक बैठे रहने से ग्लूटियल मांसपेशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियां कमजोर होने से चलने व संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती हैं।

प्रत्येक पैर को 5 बार उठाएं।

ऑबलिक ट्रिप्स
यह एक्सरसाइज आपके पेट के दोनों तरफ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अपने पैरों को कुर्सी के किनारे पर फर्श पर सपाट रखें। एब्स को सिकोड़ते हुए 45 डिग्री के कोण पर बैठें। अपने हाथ को अपने सामने लींग रखें। हाथ को शरीर के साथ सीधा रखें हीरे-धीरे दाईं ओर मुड़ें। 10 सेकंड के लिए स्थिर रहें। अब बायीं ओर ऐसा करें। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें।
डेस्क प्लॉक्स: यह व्यायाम आपके कंधों और कोर के लिए फायदेमंद है। अपने शरीर को सीधा रखें हुए अपनी डेस्क पर झुकें। पीठ सीधी होनी और बाजू का आगे का हिस्सा सतह के विपरीत होना चाहिए। हाथ शरीर के दोनों ओर होने चाहिए। इस मुद्रा में कम से कम 30-45 सेकंड तक रहें।
चेयर काफ रेजेज
यह व्यायाम पिंडलियों को मजबूत करने के साथ आपको सक्रिय रूप से दौड़ने, कूदने और संतुलन बनाने में मदद करता है। पीठ को सहारा न देते हुए अपनी कुर्सी पर सीधे बैठें 4 पैर कंधे की चौड़ाई जितना अलग हों। एडियों को धीरे-धीरे उठाएं। इसी अवस्था में रहें। वजन बढ़ाने के लिए गोद में कोई भारी चीज रखें। □□

शेष...पाकिस्तान लौट रहे नवाज शरीफ....

वह वापस आ रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि नवाज शरीफ समझते हैं कि यह समय उनकी देश वापसी के लिए सबसे उपयुक्त है और उन्हें देश के किसी वर्ग की ओर से विशेष विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पत्रकार और विश्लेषक सलमान

शेष...एक साल के भीतर.....

ने इस मामले में रिस्पांस दिया है। बच्चों ने अपनी गुल्लकों में से पैसे निकालकर दिए हैं। कर्मचारियों ने वेतन का अंश दिया है। कई पेंशन दारकों ने अपनी पेंशन में से पैसे दिए। मेरी माता जी ने 51 हजार दिए हैं। मैं इस समर्थन के लिए जनता का

गनी का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी की घोषणा मुसलिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है जिससे यह साफ होता है कि नवाज शरीफ की देशवासी से संबंधित खतरा खत्म हो चुका है। □□

शेष...सुमित नागल बोले

एक करोड़ रुपए तक है और यह भी तब है, जब मैं केवल एक कोच के साथ यात्रा करता हूं। मैंने जो भी कमाया, उसे खर्च भी कर दिया। नागल ने कहा- मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत का नंबर एक खिलाड़ी होने के बावजूद मुझे पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं ग्रैंड स्लैम के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हूं। मैंने पिछले साल ओलिंपिक में एक मैच

भी जीता था। इसके बावजूद को भी विश्वास नहीं था कि मैं वापसी कर सकता हूं। यह निराशाजनक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह पर्याप्त नहीं है। भारत में वित्तीय सहायता हासिल करना, बहुत मुश्किल है। ईमानदारी से कह तो मुझे पता नहीं कि क्या करना है। मैंने हार मान ली है। नागल को पिछले साल कोर्ट से बाहर की समस्याओं से भी जूझना पड़ा। □□

शेष...पाकिस्तान का 'हैरी पॉटर'...

का विकेट ले चुके हैं। उनकी लेग ब्रेक और गुगली की ग्रिप भी एक सी है। फर्क यह है कि वह गुगली के लिए बैक हैंड का इस्तेमाल करते हैं जिससे आम तौर पर यह अंदाजा लग जाता है कि वह गुगली गेंद करने वाले हैं। फ्लाइट उनका अन्य हथियार है। ऐसी गेंदों पर बल्लेबाज का उनके सामने फॉर्मर्वर्ड डिफेसिव शॉट खेलना उतना आसान नहीं रहता। ऐसे मौकों पर उनकी तेज टर्न काफी खतरनाक होती है जिनमें ज्यादातर मौकों पर गेंद बल्लेबाज के बैट और पैड के बीच से निकल जाती है।

भारतीय उप महाद्वीप में खूब रन

बना चुके जो रुट और जैक क्राले को वह कुछ इसी तरह आउट कर चुके हैं। उनकी ऐसी ही एक गेंद को बेन स्टोक्स लेग पर डिफेंस करने गए लेकिन गेंद पिंडिल और ऑफ स्टम्प की ओर गई जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। पाकिस्तान ने पिछले साल टेस्ट के मास्टर गेंदबाज नसीम शाह को बनडे में उतारने का प्रयोग किया था जो काफी सफल रहा था। ऐसे में यह उम्मीद बंधती है कि हैरी पॉटर की तरह दिखने वाले अबरार को वर्ल्डी कप के दल में उतारना पाकिस्तान के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। □□

शेष...मंजूर पस-मंजूर

पर आधारित विकास के लिए काम कर रहे जी20 का नई दिल्ली घोषणापत्र भी इसके घोषित लक्ष्यों के अनुरूप है। इस आयोजन में यह भी उम्मीद थी कि सदस्य देशों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी एक स्पष्ट राय सामने आएगी। इस मसले पर समूह के बाली में हुए पिछले शिखर सम्मेलन के रुख को ही दोहराया गया कि सभी देशों को किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों का उपयोग या इसकी धमकी अस्वीकार्य है। इसके अलावा, सभी नेताओं ने आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया।

जाहिर है, मौजूदा विश्व में गंभीर चुनौतियों को संबोधित करते हुए सम्मेलन में फिर से व्यापक महत्व के मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर

सहमति बनी है। जी-20 सम्मेलन से इतर भारत के लिए यह मौका कूटनीतिक तौर पर एक अतिरिक्त अवसर था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच सीधी बातचीत को एक अहम पक्ष के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इसमें दोनों देशों ने विश्व कल्याण, रक्षा साक्षेदारी को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर साथ काम करने का संकल्प लिया। अमेरिका के अलावा भारत ने कई अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें आने वाले समय में दुनिया भर में आर्थिक, स्वास्थ्य, सामरिक और अन्य क्षेत्रों में उभर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए नए आधुनिक तकनीकी संसाधनों से लेकर कूटनीतिक स्तर पर नई रूपरेखा के लिए सहमति बनी। कहा जा सकता है कि जी-20 अपने घोषित उद्देश्यों को अब वैश्विक परिदृश्य में नया स्वरूप दे रहा है और भारत इसमें अब केंद्रीय भूमिका में है।

सात साल पुराने अलाई दरवाजे का किया जाएगा संरक्षण कार्य

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महाराष्ट्रीय कुतुबमीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी की ओर से बनवाए गए अलाई दरवाजे के संरक्षण का कार्य कराएगा। इस कार्य के अगले कुछ माह में शुरू हो जाने की उम्मीद है। एएसआई ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। इसके तहत दरवाजे के बाहरी भागों से उत्तर चुके प्लास्टर व पत्थर को ठीक किया जाएगा। पहले चरण में जमीन की सतह से पांच फीट से ऊपर वाले हिस्से का कार्य किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में पांच फीट से नीचे के भाग में काम होगा। ऐसा काम की जटिलता को देखते हुए किया जा रहा है। इस दरवाजे की दीवारों की ऊपरी सतह पर नक्काशी वाले पत्थर लगे हैं। पुरानी फोटो देख कर तथा इसके निर्माण के बारे में दस्तावेजों में वर्णित जानकारी के आधार पर उसी तरह से नक्काशी कर पत्थर लगाए जाएंगे। इस कार्य के लिए एएसआई मुख्यालय ने दिल्ली मंडल को अनुमति दे दी है। इस दरवाजे पर 30 साल बाद काम होने जा रहा है।

अलाई दरवाजा : अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का आकर्षण और अनूठा नमूना है। यह दरवाजा सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से बना है। इस पर खूबसूरत और आकर्षक नक्काशी की गई है। कुतुबमीनार परिसर को खूबसूरत रूप देने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रोजेक्ट

इराक में शादी समारोह में आग, 100 लोग जिंदा जले

इराक के नेवेह प्रांत में आग का तांडव देखने को मिला है। शादी समारोह में आग लगने से दुल्हा-दुल्हन समेत 100 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 150 लोग झुल गए। शादी समारोह के दौरान आलग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुलसने वालों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि पटाखे जलाने की वजह से आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर स्थानीय पत्रकारों ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें इवेंट हॉल के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं। वहीं, इराकी समाचार एजेंसी नीना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौके पर मौजूद ज्वलनशील सामानों की वजह से आग भड़की।

शेष...भारत से कुछ तो सीखे पाकिस्तान

का कार्यभार संभालते देखा है। यह तब हुआ था, जब 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, इसलिए स्वतः सीनेट के अध्यक्ष गुलाम इशाहाक खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए थे।

नई दिल्ली से एक और दिलचस्प खबर आई है कि पहली बार किसी भारतीय महिला के रूप में सुश्री गीतिका श्रीवास्तव इस महीने के अंत तक इस्लामाबाद में कोई पूर्णकालिक उच्चायुक्त नहीं है। इस पद को कमतर करके अब प्रभागियों के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद में अंतिम पूर्णकालिक भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया थे, जिन्हें 2019 में निष्कासित कर दिया गया था। बाद में वह कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने और उसके बाद सेवानिवृत हो गए।

पाकिस्तान से नई दिल्ली लौटने वाले अधिकांश उत्कृष्ट उच्चायुक्तों को प्रोन्तु करके विदेश सचिव बनाया गया है। सुश्री गीतिका इस्लामाबाद में 'महिला राजनीतिक क्लब' में शामिल होंगी, जिनमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिला राजनीतिक शामिल हैं। फिलीपीस की राजदूत के बाद वह

दूसरी एशियाई सबसे वरिष्ठ महिला राजनीतिक होगी। हालांकि पाकिस्तान से आने वाली खबरें हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती हैं और मुल्क के विभिन्न हिस्सों में लगातार आतंकवादी हमले होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद को महिला राजनीतिकों सहित राजनीतिकों के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है।

इस्लामाबाद में सबसे लोकप्रिय महिला राजनीतिकों में से एक यूरोपीय संघ से हैं। राजदूत रीना कियोनका बलूचिस्तान सहित पूरे पाकिस्तान में यूरोपीय संघ की परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए अक्सर दौरा कर रही हैं।

जब मैंने उनसे सुश्री गीतिका के आने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान में अपने प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं को भेजने वाले मुल्कों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह संकेत है कि दुनिया भर में लैंगिक समानता और महिला राजनीतिक शामिल हो रही है।' सुश्री गीतिका के आगमन से ठीक पहले, ब्रिटेन ने भी पुरानी वर्जनाओं को तोड़ते हुए अपनी पहली महिला उच्चायुक्त जेन मैरियट को पाकिस्तान भेजा। □□

मंजर पस-मंजर

मीम.सीन.जीम

• हौसलों की जीत • एक नई शुरुआत • सहमति का स्वर

हौसलों की जीत

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत से निसंदेह खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और क्रिकेट प्रेमियों में अगले महीने से शुरू होने वाले विश्वकप को लेकर उम्मीदें बलवती हुई हैं। हालांकि एशिया कप के प्रदर्शन को विश्वकप मुकाबलों के पैमाने पर कस कर नहीं देखा जा सकता, मगर इसमें जिन टीमों को पराजित कर भारतीय टीम ने विजय हासिल की है, उनसे उसका वहाँ भी मुकाबला होना है। आमतौर पर भारतीय टीम का पाकिस्तान की टीम

भारतीय टीम के लिए यह बहुत आसान लक्ष्य था। मगर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जैसी तूकानी गेंदबाजी की, वैसी गेंदबाजी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम मौकों पर देखी गई है। एक ओवर में चार विकेट झटकने वाले वे दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए। सात ओवरों में उन्होंने छह विकेट लिए।

से कड़ा मुकाबला होता है। एशिया कप में वह भी थी, मगर भारतीय टीम के सामने अंतिम मैच तक नहीं पहुंच पाई। श्रीलंका की टीम भी भारत को जोरदार टक्कर देती है, मगर इस बार उसे जिस तरह पराजय का सामना करना पड़ा, उसमें कई कीर्तिमान भारतीय टीम के नाम दर्ज हो गए। अंतिम मुकाबले में श्रीलंकाई टीम केवल पचास रन बना पाई और पंद्रह ओवर तथा दो गेंदों पर ही वह मैदान से बाहर हो गई। भारतीय टीम के लिए यह बहुत आसान लक्ष्य था। मगर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जैसी तूफानी गेंदबाजी की, वैसी

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीके:-

- ① मनीआर्डर द्वारा
- ② ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SHANTI MISSION
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

गेंदबाजी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम मौकों पर देखी गई है। एक ओवर में चार विकेट झटकने वाले वे दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए। सात ओवरों में उन्होंने छह विकेट लिए।

खेल में जो टीम अपने प्रतिद्वंद्वी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब हो जाती है, उसकी जीत तय मानी जाती है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर श्रीलंका की टीम रनों का पहाड़ खड़ा करने के मंसूबे से मैदान में उतरी तो जरूर थी, मगर एक ओवर में ही चार खिलाड़ियों के बाहर हो जाने के बाद उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना बढ़ गया कि वह अंत तक उबर नहीं पाई। इसका पूरा लाभ भारतीय गेंदबाजों ने उठाया और श्रीलंकाई टीम को पचास रनों पर समेट दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे दोनों भारतीय खिलाड़ी इस आसान लक्ष्य को हासिल कर नाबाद लौटे। यह पहली बार था जब अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम के सामने कोई टीम इतने कम रनों का लक्ष्य रख पाई थी। इसके पहले श्रीलंका की ही टीम भारतीय टीम के सामने 2014 में अट्टावन रनों पर सिमट गई थी। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय खेलों में पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने दो अवसरों पर अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को दस विकेट से हराया। इसके पहले 1998 में जिम्बाब्वे की टीम को शारजाह में दस विकेट से हराया था। इस प्रतिस्पर्धा में एक बड़ा कीर्तिमान शुभमन गिल ने भी अपने नाम दर्ज किया, जिन्होंने कुल 302 रन बना कर इतिहास रच दिया।

हालांकि एशिया कप में सदा से भारत का दबदबा रहा है। उसने आठवीं बार यह कप अपने नाम किया है। श्रीलंका की टीम भी इस शमाले में बहुत पीछे नहीं है। छह बार वह भी यह कप जीत चुकी है। पाकिस्तान महज दो बार इस कप पर कब्जा जमा पाया है। ये तीनों टीमें विश्वकप मुकाबले में भी उतरेंगी। इस तरह एशिया कप मुकाबले के अनुभवों से इन टीमों को विश्वकप प्रतिस्पर्धा में अपना प्रदर्शन सुधारने का एक आधार मिलेगा। आजकल खेल तकनीक

पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इसलिए खिलाड़ियों को एशिया कप में अपने प्रदर्शनों का मूल्यांकन करते हुए अपने तकनीकी कौशल को बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धी टीम के खिलाड़ियों की कमजोरियों और खूबियों को समझने का भी अवसर मिलेगा। हालांकि किसी भी प्रतिस्पर्धा को अगली प्रतिस्पर्धा की कसौटी नहीं माना जाना चाहिए। पर एशिया कप में मिली विजय से भारतीय खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ा ही है।

एक नई शुरुआत

संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्यवाही संसद के नए भवन में होगी। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के अनेक सांसदों ने अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनवाए गए संसद भवन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया और इस दौरान उन उपलब्धियों को भी रेखांकित किया, जो बीते सात दशक से अधिक समय में देखने को मिलें। इसमें कोई सदेह नहीं हो सकता कि विभिन्न सरकारों की ओर से संसद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण ही आज देश इस पड़ाव पर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, वह पूरा होता दिख रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष-विपक्ष के अनेक नेताओं ने संसदीय यात्रा के 75 वर्ष के लिए सफर की चार्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए।

राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए। संसद का नया भवन भव्य है और वह कहीं अधिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन उसकी गरिमा तब बढ़ेगी, जब पक्ष-विपक्ष आम सहमति की राजनीति की महत्ता को समझेंगे। एक समय था, जब संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वस्थ एवं सार्थक विचार-विमर्श होता था।

यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद में आम सहमति के मुश्किल से ही कायम हो पाती है। वहाँ आजकल खेल तकनीक

हंगामा और नारेबाजी ही अधिक होती है। ऐसा इसीलिए होता है, क्योंकि विरोध के लिए विरोध की राजनीति हावी होती जा रही है। यह राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। संसद सही तरह तभी चल सकती है और विधेयकों के साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर आम सहमति तभी कायम हो सकती है, जब सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों एक-दूसरे को अपेक्षित महत्व देंगे। लोकतंत्र में असहमति के बीच सहमति कायम करनी होती है। आज जब सभी यह मान रहे हैं कि अतीत में संसद में कहीं अधिक सार्थक चर्चा होती थी, तब फिर इसके लिए सभी को सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए कि वह सुनहरा दौर संसद के नए भवन में भी देखने को मिले? निःसंदेह ऐसा तभी हो सकता है, जब राजनीतिक कटुता और नकारात्मक राजनीति का परित्याग किया जाएगा।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव शीघ्र होने हैं और लोकसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दल संसद और साथ ही जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग एवं संवेदनशील हों तो संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दल संसद और साथ ही जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग एवं संवेदनशील हों तो संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए।

सहमति का स्वर

उम्मीद के मुताबिक जी-20 के शिखर सम्मेलन में जिन बातों पर आज देश इस पड़ाव पर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, वह पूरा होता दिख रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष-विपक्ष के अनेक नेताओं ने संसदीय यात्रा के 75 वर्ष के लिए सफर की चार्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए। संसद का नया भवन भव्य है और वह कहीं अधिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन उसकी गरिमा तब बढ़ेगी, जब पक्ष-विपक्ष आम सहमति की राजनीति को समझेंगे। एक समय था, जब संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वस्थ एवं सार्थक विचार-विमर्श होता था।

यह भी अतिरिक्त अवधि के लिए एक अतिरिक्त अवधि है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच सीधी बातचीत को एक अहम पक्ष के रूप में दर्ज किया जा सकता है। विश्व में गंभीर चुनौतियों को संबोधित करते हुए सम्मेलन में फिर से व्यापक महत्व के मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर सहमति बनी है। जी-20 सम्मेलन से इतर भारत के लिए यह मौका कूटनीतिक तौर पर एक अतिरिक्त अवसर था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच सीधी बातचीत को एक अहम पक्ष के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

दरअसल, नई दिल्ली घोषणापत्र जिन बिंदुओं पर केंद्रित है, उन्हें विश्व भर में समावेशी विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके मुख्य केंद्रीय मुद्दों में मजबूती, दीर्घकालिक संतुलित और समावेशी विकास के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, इकीकारणी सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि शामिल हैं। जाहिर है, आर्थिक सहयोग मुद्दों में जबकि दूसरे विकास के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, इकीकारणी सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि शामिल हैं। जाहिर है, आर्थिक सहयोग मुद्दों में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, इकीकारणी सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि शामिल हैं। जाहिर है, आर्थिक सहयोग मुद्दों में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, इकीकारणी सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि शामिल हैं। जाहिर है, आर्थिक सहयोग मुद्दों में तेजी, दीर्घक